



हंगामे के कारण 4 बार स्थगित हुई संसद

पेपर लीक पर कड़े प्रावधान वाला संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

नयी दिल्ली । सरकार ने परीक्षाओं में पेपरलीक और संगठित परीक्षा धांधली पर कड़ा शिकंजा कसने के उद्देश्य से सोमवार को लोकसभा में %लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कर्मिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। इसमें दोषियों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने, संपत्ति जब्ती, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों, समयबद्ध जांच और सुनवाई सहित कई नए सख्त प्रावधान किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। इन्हें रोकने और दोषियों के खिलाफ शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। विधेयक लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।संशोधन विधेयक के तहत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस कानून के तहत

हंगामा नहीं चर्चा करें...



अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अधिसूचित करने का अधिकार है। अदालतों में मामलों की सुनवाई दिन- प्रतिदिन के आधार पर होगी और आरोपपत्र दाखिल होने से तीन महीने में मामले का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ

नई दिल्ली । संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने सोमवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से फिर अपील की कि वे संसद में हंगामा करने के बजाय पब्लिक एजामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लें।उन्होंने कहा कि कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक देशभर के छात्रों की चिंताओं को दूर करने और पेपर लीक में शामिल दोषियों को समयबद्ध व सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। रिजिजू ने इस विधेयक पर विपक्ष से खुली चर्चा करने के लिए आग्रह किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि आज, देश भर के छात्रों की चिंताओं को देखते हुए, पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जा रहा है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कुछ सदस्य इस पर चर्चा करने से की बजाय हंगामा कर रहे हैं।



ही उच्च न्यायालय में दायर अपीलों का भी तीन महीने के भीतर निस्तारण करने का प्रावधान है। विधेयक केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर किसी मामले की जांच के लिए विशेष कार्यबल (स्पेशल टास्क फोर्स) गठित करने की शक्ति भी देता है। इसके अलावा कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए एक या अधिक विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का अधिकार भी दिया जाएगा।

विधेयक में संगठित तरीके से पेपर लीक, परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल कराने या ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों के लिए सजा

बढ़ाकर दो वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास तथा एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना करने का प्रस्ताव है। अदालत भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त दंड भी दे सकेगी।

विधेयक के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि कोई सेवा प्रदाता संस्था, एजेंसी या कंपनी इस प्रकार के अपराध में शामिल पाई जाती है तो उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा आयोजित करने में आई वास्तविक लागत की वसूली भी संबंधित सेवा प्रदाता से की जाएगी और उसे चार वर्ष तक किसी भी परीक्षा से जुड़े कार्यों से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल प्रदेश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जनजातीय पर्यटन विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में भारत के प्रतिष्ठित पर्यटन व्यापार मेले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट (आईआईटीएम) बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रदेश की समृद्ध पर्यटन संभावनाओं, निवेश के अवसरों और विशिष्ट पर्यटन उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन किया।

प्रमुख समाचार

लोकसभा अध्यक्ष ने स्वर्ण पदक विजेता चानू को बधाई दी

नईदिल्ली। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू समेत अन्य पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सोमवार को लोकसभा में बधाई दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है।” उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानमबम और राजा मुथुपांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पॉवर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

नीट मामला : संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन

नईदिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली में नीट-यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर बीते 20 जुलाई को बलप्रयोग किए जाने को लेकर सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर ‘वोट चोरी, पेपर चोरी, चंदा चोरी’ लिखा हुआ था। उधर, कांग्रेस सांसदों- रणदीप सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन और रेणुका चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थान के नोटिस दिए थे। इन नोटिस में सूचीबद्ध कार्यवाही को स्थगित कर छात्रों के खिलाफ “बर्बरता” के मुद्दे पर चर्चा कराने और गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही तय करने की मांग की गई। राहुल गांधी ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए “बर्बर हमले” की जवाबदेही तय करने की मांग की थी।

नीट संकट के बीच संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान

नईदिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद के कारण इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान का सोमवार को एनडीए नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी के साथियों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाकर और सम्मान देकर उनका स्वागत किया। प्रधान के आने से पहले ही कई भाजपा और एनडीए सांसद संसद के मकर द्वार पर जमा हो गए थे। जैसे ही वे संसद परिसर में दाखिल हुए, सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्हें अंदर तक साथ ले गए और एक खास टोपी पहनाई। शिक्षा चोरी के नारे लगाते हुए, विपक्षी सांसदों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद कैसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों पर एके-47 चलाने वाला जवान निलंबित

पटना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शन भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी नतीजे अभी भी सामने आ रहे हैं। बिहार के सिवान ज़िले में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के एक जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि उसने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एके-47 राइफल से गोली चलाई थी। सिवान में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना में तीन छात्र घायल हो गए थे और इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। हिंसा से निपटने के तरीके को लेकर बढ़ते दबाव के बीच यह संस्पेशन हुआ है। सस्पेंड किए गए कर्मचारी की पहचान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य अभिषेक पटेल के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक, सिवान में हुई हिंसा के दौरान पटेल ने कथित तौर पर एके-47 से प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाई थी। इस फायरिंग में तीन छात्र गोली लगने से घायल हो गए और अभी पटना के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फायरिंग की घटना के सिलसिले में यह पहली बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई है।

ई20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली में 1 अगस्त को टाउन हॉल

नईदिल्ली। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि पार्टी सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए 1 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में ई20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित करेगी। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है और धर्मेंद्र प्रधान को जनता के सामने इस्तीफा देना पड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि वे इस मौके का फायदा उठाकर ई20 फ्यूल से जुड़े मामले पर भी स्थिति साफ करें। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है; उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं... इसलिए, मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि वे आगे आएँ और इस समस्या के और बढ़ने से पहले इसे हल करें। इस मामले पर सभी को एक साथ लाने के लिए, हम इस शनिवार को ई20 के खिलाफ नेशनल टाउनहॉल आयोजित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह दोषधर 12:00 बजे शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आस-पास के शहरों में रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं, उन्हें सुबह 11.30 बजे तक कॉन्स्ट्रिक्ट्यूशन क्लब पहुंचना चाहिए।



हरबंश दीक्षित

प्रश्नपत्र की रक्षा करोड़ों युवाओं के विश्वास की रक्षा है। यह संचिधान प्रदत्त समान अवसर की रक्षा है। यह भारत की प्रतिभा, प्रशासनिक गुणवत्ता और लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा है। पेपर लीक से निपटने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शिक्षण संस्थान, कोचिंग उद्योग और स्वयं छात्रों की भी है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी बनाने के लिए ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ को और प्रभावी बनाने हेतु उपस्थक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इन प्रस्तावों का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वे दंड बढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि वे परीक्षा-

अपराधों के प्रति शासन की गंभीरता का स्पष्ट संकेत देते हैं। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, व्यक्तिगत सल्लसता के मामलों में न्यूनतम कारावास की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाने तथा गंभीर मामलों में आर्थिक दंड को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है। संगठित तरीके के जुर्माने की व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि अब परीक्षा अपराधों को सामान्य धोखाधड़ी नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक अपराध माना जा रहा है। दोषी एजेंसियों की संपत्ति कुर्क करने, उनके प्रबंधन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करने तथा विशेष अदालतों को अधिक प्रभावी वैधानिक अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव भी इसका हिस्सा है। इन

संशोधनों का सबसे उल्लेखनीय पक्ष ‘समयबद्ध न्याय’ की अवधारणा है। वर्षों तक लंबित मुकदमे अपराधियों में भय नहीं, बल्कि साहस पैदा करते हैं। इसलिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से तीन माह के भीतर सुनवाई पूरी करने की व्यवस्था केवल प्रक्रियागत सुधार नहीं, बल्कि न्याय की प्रभावशीलता की बहाली का प्रयास है। इसके साथ ही निर्दोष विद्यार्थियों को अनावश्यक तथै दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षा प्रावधानों पर बल दिया जाना दर्शाता है कि कानून का उद्देश्य केवल दंड नहीं, बल्कि न्याय भी है।

वस्तुतः ये प्रस्ताव शासन की उस नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें राज्य अपराध की संभावना को न्यूनतम करने वाला उत्तरदायी संरक्षक बनता है। यह दंडात्मक शासन से आगे

सुरक्षा को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना का दर्जा दिया जाए। प्रश्नपत्र केवल मुद्रित कागज नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील डिजिटल दस्तावेज है। उसके निर्माण, एन्क्रिप्शन, भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए वही सुरक्षा मानक अपनाए जाने चाहिए, जो बैंकिंग, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए लागू होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी इस दिशा में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है। एआई संधिध्व गतिविधियों का विश्लेषण कर सकती है, प्रतिक्रुपण की पहचान कर सकती है, साइबर हमलों की पूर्व चेतावनी दे सकती है और परीक्षा प्रक्रिया की सतत निगरानी कर सकती है। किंतु तकनीक उपयोग सदैव पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और



मानवीय नियंत्रण के साथ होना चाहिए। तकनीक का उद्देश्य न्याय को सशक्त करना है, उसका स्थान लेना नहीं। इसके साथ ही प्रत्येक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा का नियमित मूल्यांकन, केंद्र और राज्यों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा ग्रिड तथा स्पष्ट प्रशासनिक जवाबदेही की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। परीक्षा माफिया सीमाओं में नहीं बंधे हैं, इसलिए सुरक्षा तंत्र भी समन्वित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और अखिल भारतीय होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। प्रतियोगी परीक्षाएं इन दोनों संवैधानिक आदर्शों की व्यावहारिक

अभिव्यक्ति हैं। जब प्रश्नपत्र पहले से कुछ लोगों तक पहुंच जाता है, तब केवल परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि संविधान की मूल भावना भी आहत होती है। इसीलिए परीक्षा सुधार एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी प्रौद्योगिकी-सक्षम, पारदर्शी और विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली का समर्थन करती है। दूसरी ओर, आधार, यूपीआई और डिजिटल अवसंरचना ने सिद्ध किया है कि भारत विशाल स्तर पर सुरक्षित डिजिटल प्रणालियां विकसित करने में सक्षम है। यही क्षमता अब परीक्षा प्रणाली में भी दिखाई देनी चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता को लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला माना है।

कभी नक्सलियों का डॉक्टर रहा कुंवर सिंह, अब सड़क हादसे में घायल मजदूर की बचाई जान

कांकेर। जिले के भानुप्रतापपुर में मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक पूर्व नक्सली ने सड़क हादसे में घायल मजदूरों का इलाज किया। कभी नक्सली संगठन में डॉक्टर के रूप में काम करने वाला कुंवर सिंह घायल मजदूर की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया [जानकारी के अनुसार, भानुप्रतापपुर के समीप मुल्ला स्थित पुनर्वास केंद्र में निर्माण कार्य कर रहा एक मजदूर अपने साथी के साथ दोपहर का भोजन कर बाइक से कैप लौट रहा था। इसी दौरान कैप के सामने एक ट्रक से बचने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हालांकि दोनों ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुनर्वास केंद्र में रह रहे आत्मसमर्पित पूर्व नक्सली मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल मजदूर को सुरक्षित उठाकर कैप के अंदर



पहुंचाया। इसके बाद कंपनी नंबर-5 में कभी डॉक्टर रहे कुंवर सिंह और पत्नी ने घायल का प्राथमिक उपचार किया और उसकी देखभाल की। कुंवर सिंह ने बताया कि नक्सली संगठन में रहते हुए वह कंपनी नंबर-5 में डॉक्टर के रूप में कार्य करता था।

मुठभेड़ों में घायल हुए नक्सलियों का इलाज करना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने बताया कि कई बार जंगलों में ही ऑपरेशन कर नक्सलियों के शरीर से गोलिएं निकालीं। उसके अनुसार उसने सेंट्रल कमेटी सदस्य संग्राम, सुजाता और मनोज सहित कई

बड़े नक्सली नेताओं और दर्जनों नक्सलियों का उपचार किया था।अब मुख्यधारा में लौटने के बाद वही अनुभव उसने एक घायल मजदूर की जान बचाने में लगाया। ये पुनर्वास की सफलता और जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है।

एआई से फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी



दुर्ग। छावनी थाना पुलिस ने एआई से फोटो एडिट कर पैसे की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी, पीड़िता को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था। भिलाई के छावनी थाना की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कराई कि उसके साथ काम करने वाला युवक उससे पांच लाख की मांग कर रहा है।

आरोपी रकम नहीं देने पर एएआई से उसकी फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। युवती ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि वह उसके पति को जान से मारने और जबरन तलाक देने का दबाव भी बना रहा है।छावनी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को धमका से

गिरफ्तार किया। दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को धमका से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह पीड़िता से एक तरफा प्यार करता है और दोनों फाइनेंस कंपनी में एक साथ काम करते थे। इसके बाद युवती ने शादी का ली। जिसके बाद से वह युवती को परेशान करने लगा। उसने युवती को डराने के लिए एआई से फोटो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी और उससे 5 लाख की मांग की। आरोपी ने पैसे नहीं देने पर पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी और उससे जबरन तलाक देने की भी धमकी के लिए भी दबाव बनाने की बात कबूल की।

जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई

55 किलो गौमांस के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार



जशपुर। जिले के कोतबा चौकी क्षेत्र में गौमांस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम बैगाबहार में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 55 किलो गौमांस के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक समेत कई सामान बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि ग्राम बैगाबहार और रोकबहार के कुछ लोग तड़के 3-4 बजे के बीच एक गौवंश को बरगोड़ा क्षेत्र में ले जाकर उसका वध कर रहे हैं। उसका मांस काटकर अपने घर ले जाने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही चौकी कोतबा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी रंजीत एक्का की बाइक की तलाशी ली, जिसमें रखी एक बोरी में गौमांस बरामद हुआ। पूछताछ में रंजीत एक्का ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही एक गौवंश का वध किया था। इसके बाद पुलिस

ने मौके से कुल 55 किलो गौमांस, घटना में इस्तेमाल बाइक, मांस काटने में इस्तेमाल की गई टांगी, छुरी, रस्सी और गौमांस की बिक्री से प्राप्त 2,000 रुपए जब्त कर लिए।इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में रंजीत एक्का (31 साल), राकेश तिकी (24), मेघनाथ तिकी (41), विनय तिग्गा (26), अमलेश तिग्गा (32), हीरालाल तिकी (45 साल) सभी निवासी ग्राम

बैगाबहार शामिल हैं। वहीं मनमोहन तिग्गा (32 साल) और अन्नाराम कुनूर (31) निवासी ग्राम रोकबहार और संजय तिग्गा (26), अनूप भगत (21) निवासी हाईस्कूल पारा, कोतबा भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी 10 आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक ण्णु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5, 6 एवं 10 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर

न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई में थाना तुमला पुलिस का भी विशेष सहयोग रहा।

एसएसपी डॉ। लाल उमेद सिंह ने बताया कि ऑपरेशन शंखनाद के तहत ये कार्रवाई की गई है। गौवंश से जुड़े अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प से कई घायल

बलरामपुर। जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंदला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जहां दोनों पक्षों ने लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किए जाने का भी आरोप है। जानकारी के अनुसार, गोंदला गांव में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद को लेकर रविवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडों से जमकर प्रहार किए गए। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मारपीट के दौरान ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश किए जाने से स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस संभार धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच भी जारी है।

बस्तर संभाग में मलेरिया के 8426 मरीज पॉजिटिव मिले

कांकेर। जिले के मर्दापोटी बालक आश्रम में पढ़ने वाले चौथी कक्षा के छात्र सुभाष कुमेटी (9) की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में दो दिन में मलेरिया से दो बच्चों की जान जा चुकी है। बीते 10 दिनों में यह तीसरी मौत है, तीनों मृतक स्कूली बच्चे हैं। वहीं छात्रावास के 11 बच्चे पॉजिटिव पाये गये हैं। मलेरिया के मरीज मिलने के बाद कांकेर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर विभाग अलर्ट मोड पर है। सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। कांकेर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मर्दापोटी और इरादाह छात्रावास में कुल 11 छात्र मलेरिया संक्रमित मिले हैं। प्रभावित छात्रावासों और गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैप लगाकर इलाज कर रही हैं। जांच करने के साथ ही दवायें बांटी जा रही हैं। सभी छात्रावासों में विशेष निगरानी बरती जा रही है। स्वास्थ्य जांच में मलेरिया पॉजिटिव मिले तामेश्वर भास्कर (7) और विक्रम मंडवो (8) की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायपुर रेफर किया गया है।

साई मंदिर में तीन दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जुलाई तक

जगदलपुर। बस्तर जिला मुख्यालय के धरमपुरा मार्ग में स्थित साई बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक तीन दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव में विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक, पालकी यात्रा, भजन संध्या, महाआरती, प्रसाद वितरण और पौधरोपण जैसे कार्यक्रम होंगे। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह काकड़ आरती से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिनभर दर्शन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहेंगे। शाम को भजन संध्या एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। रात्रि में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा।मंदिर समिति के अनुसार इस तीन दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 28 जुलाई को सुबह काकड़ आरती, विशेष अभिषेक एवं गुरु पूजन से होगी। दोपहर को मंदिर से करीब 8 किमी की पालकी व कलश यात्रा निकलेगी। 29 जुलाई को दिनभर धार्मिक अनुष्ठान, भजन संध्या और महाआरती होगी। इससे पहले दोपहर की आरती के बाद महाभंडारा होगा।

2 साल की सजा के खिलाफ 24 साल तक लड़ा केस

हाईकोर्ट ने दी राहत, लेकिन 4 महीने के लिए जाना पड़ेगा जेल

बिलासपुर। धमतरी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के 24 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए गए दीपक कुमार ओझा को ट्रायल कोर्ट ने 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए दीपक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब 24 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उच्च न्यायालय ने उसे आंशिक राहत देते हुए सजा को घटाकर 4 महीने कर दिया। कोर्ट ने उसे 30 सितंबर 2026 तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है, ताकि वह अपनी शेष सजा पूरी कर सके। हाईकोर्ट ने प्राणघातक हमले के आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 24 वर्ष पुराना मामला



होने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत का हवाला देते हुए कहा, कि सजा का मकसद एक असरदार रोकथाम बनाना है ताकि भविष्य में ऐसे ही क्राइम/कार्रवाइयों को रोका जा सके। सजा देते समय ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सजा बहुत ज्यादा सख्त न हो, लेकिन साथ ही, यह इतनी हल्की भी न हो कि इसका रोकथाम वाला असर कम हो जाए। इसके साथ अपील करने वाले को चार माह कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उसके जेल में निरुद्ध समय को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया है। अपीलकर्ता गुरु उर्फ राहुल उर्फ प्रवीण कुमार शिंदे निवासी

बांसपारा धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी का 3 दिसंबर 2002 को दीपक कुमार ओझा के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद, जब दीपक ओझा अपने घर जा रहा था और वह अपने घर के सामने पहुंचा, तो आरोपी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और उसके साथ दो और लोग थे, जिन्होंने पीड़ित पर तलेवार से हमला किया, जिसका मकसद उसे जान से मारना था। पीड़ित ने खुद को हमले से बचाने के लिए अपनी हाथ से हमले को रोका और उसकी कोहनी में गंभीर चोट आई और फेंकर भी हो गया। घायल के रिपोर्ट पर धमतरी कोतवाली पुलिस ने धारा 307/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया। सीजेएम कोर्ट ने मामले को विचारण के लिए रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय भेजा। सुनवाई उपरांत ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दो वर्ष कैद एवं 500

रू अर्थदंड की सजा सुनाई।सजा के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील में कहा गया कि उसने जमानत में मिली आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। पिछले 25 वर्ष से हर सुनवाई में उपस्थित हो रहा है। इस आधार पर सजा में छूट देने अनुरोध किया गया। जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास ने सुनवाई में पाया कि अपराध गंभीर था। इस कारण से आरोपी को कैद की सजा से छूट देने पेश आवेदन को खारिज किया। कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत का उल्लेख करते हुए इसे रिजेक्ट किया है। लेकिन, यह देखते हुए कि घटना साल 2002 की है और करीब 24 साल बीत चुका है, और अपील करने वाले का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि अभियोजन ने अपील करने वाले का कोई क्रिमिनल गतिविधि रिकॉर्ड में नहीं ला पाया है।



जगदलपुर। जगदलपुर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण के तहत बड़ी संख्या में सनातन समाज से जुड़े लोगों ने नगर में रैली निकालकर कलेक्टर परिसर पहुंचे, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिले के सवा लाख लोगों का हस्ताक्षरयुक्त जापन सौंपा। अभियान का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देते हुए देशभर में गौ हत्या

पर प्रभावी रोक लगाना है। जिला प्रभारी दीपक पनपालिया ने बताया कि यह देशव्यापी शांतिपूर्ण और गैर-राजनीतिक अभियान है, जो एक साथ देश के सैकड़ों जिलों में चलाया जा रहा है। बस्तर जिले से भी एक लाख पच्चीस हजार से अधिक लोगों के हस्ताक्षर अभियान के समर्थन में जुटाए गए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित

लगाने का निर्णय लिया। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि शराब के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और सामाजिक वातावरण भी प्रभावित होता है।

बैठक में समाज के प्रमुखों ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य किसी पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को कर्ज के बोझ से बचाना, उनकी जमीन और आजीविका की सुरक्षा करना तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि बैगा समाज आधुनिकता के साथ आगे बढ़ेगा लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और मांर की मधुर धुन को नहीं छोड़ेगा।

बैठक में सेक्टर भोरमदेव के अध्यक्ष शुक्लादा बैगा, संरक्षक कृष्णा बैगा, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं जिला संरक्षक कामू बैगा, झुलाराम बैगा सहित समाज के पदाधिकारी, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने सर्वसम्मति से नए सामाजिक नियमों का पालन करने का संकल्प लिया।

घड़ी चौक में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हिरण की मौत

कार चालक की पहचान जुटा रहा कांकेर वन विभाग

कांकेर। शहर के घड़ी चौक के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक हिरण की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद शहर में वन्यजीवों की सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हिरण अचानक सड़क पार करने के लिए दौड़ता हुआ आया। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हिरण कई फीट दूर उछलकर सड़क पर जा गिरा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह उठकर लड़खड़ाते हुए कुछ दूर तक भागा, लेकिन अधिक चोट लगने के कारण थोड़ी ही देर बाद सड़क किनारे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांकेर शहर से लगे



जंगलों से भटककर हिरण शहर में पहुंच गया था। व्यस्त सड़क पार करने के दौरान वह तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम करवाया। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कांकेर वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) रौनक गोयल ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हिरण जंगल से भटककर शहर में पहुंचा था। सड़क पार करते समय वह अचानक कार के सामने आ गया, जिससे यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

वित्त मंत्री ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किया सादर नमन

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, ‘मिसाइल मैन’ एवं ‘भारत रत्न’ से अलंकृत डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी का जीवन ज्ञान, विज्ञान, राष्ट्रसेवा और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने वैज्ञानिक योगदान, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रेरक व्यक्तित्व से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम जी का यह प्रेरक विचारकू जीवन में सफलता का आनंद तभी आता है, जब वह सफलता कठिनाई से प्राप्त की जाती है। प्रत्येक युवा को कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी के आदर्श, उनके विचार और राष्ट्रनिर्माण के प्रति उनका समर्पण सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका प्रेरणादायी जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज बना रहेगा।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में मानवाधिकार जागरूकता कार्यशाला



2, रायपुर में शिक्षकों के लिए मानवाधिकार जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालय में सुरक्षित, समावेशी, संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु शिक्षकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय के प्राचार्य श्री सुजीत सक्सेना द्वारा मुख्य अतिथि एवं प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. कन्हैया त्रिपाठी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत कर किया गया। प्राचार्य ने अपने स्वागत उद्बोधन में डॉ. त्रिपाठी के मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं उपलब्धियों से शिक्षकों को अवगत कराया। मुख्य वक्ता डॉ. कन्हैया त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भेदभाव-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक शिक्षक का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने बच्चों के अधिकार, लैंगिक समानता, गरिमापूर्ण व्यवहार, बाल संरक्षण, संवेदनशील शिक्षण, डिजिटल सुरक्षा तथा जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

राजधानी के अशोका आइकन में दिनदहाड़े चोरी, सोने-चांदी के जेवरतार पार

रायपुर। राजधानी के मोवा स्थित अशोका आइकन में करोड़ों की चोरी की वारदात सामने आई है। दिनदहाड़े घर में अलमारी तोड़कर 51.50 रुपए कैश समेत सोने-चांदी के जेवरतार पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत 70 लाख रुपए आंकी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, घटना उस वक्त हुई जब परिवार नया रायपुर किसी काम से गया हुआ था। वापस आने पर उनके होश उड़ गए। अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसमें रखे 51।50 लाख कैश और सोने-चांदी के जेवरतार गायब थे। उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने घर में काम करने वाले रसोइए महेंद्र कुमार यादव पर चोरी का आरोप लगाया। आशंका जताई कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोसाइटी में आने-जाने वाली की डिटेल्स के साथ सीसीटीवी फेमेरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मी आरोपी और उसके साथियों की तलाश में जुटे गए हैं।

छत्तीसगढ़ फिकबॉक्सिंग संघ का चुनाव, छगन मूंदड़ा फि्ट बने प्रदेश अध्यक्ष



रायपुर। किकबॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की वार्षिक साधारण सभा की बैठक एवं चुनाव सोमवार को हुआ। चुनाव अधिकारी अनिल मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक संचालक (खेल), लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि एसोसिएशन की नई प्रबंध कारिणी का चुनाव सत्र 2026 से 2030 के लिए संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा नामित पर्यवेक्षक प्रवेश जोशी, सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर की उपस्थिति में हुआ। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से छगन मूंदड़ा को पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया। कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर तारकेश मिश्रा, महासचिव आकाश गुरुदीवान एवं कोषाध्यक्ष प्रभात साहू चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर मनीष बाग, रघुनाथ नायक, व्यंकैश दास मानिकपुरी, संकल्प तिवारी तथा संयुक्त सचिव के लिए प्रीति मिश्रा, रोशनी सेन, स्वाति राजवाड़े, अमन सोनी चुने गए। सरवर एक्का, मयंक डडसेना, भानु प्रताप साहू, एवं ममता सिंह ठाकुर को कार्यकारिणी सदस्य में स्थान मिला।

राजधानी/छत्तीसगढ़

जिस समाज की महिलाएं सक्रिय, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता: रमन

महाराष्ट्र मंडल कार्यकारिणी, समितियों व महिला केंद्रों के 225 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे स्पीकर

रायपुर। जिस समाज की महिलाएं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में सक्रिय होती हैं, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। महाराष्ट्र मंडल की समितियों, प्रकल्पों और केंद्रों में 80 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी समाज की जागरूकता का प्रमाण है। महाराष्ट्र मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में इस आशय के विचार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने व्यक्त किए। समारोह में 14 कार्यकारिणी सदस्यों के साथ 17 समितियों, 17 महिला केंद्रों और 11 प्रकल्पों के करीब 225 पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ली।

डॉ. रमन सिंह ने कहा जिस समाज के डीएनए में महान संत की साधना, वीर सावरकर– तिलक जैसे सेनानियों का शौर्य और कलाकारों की प्रतिभा हो, उस समाज का प्रोडक्ट तो महाराष्ट्र मंडल की तरह अच्छा ही होगा। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में ही महाराष्ट्र मंडल के 100 केवी सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सौर ऊर्जा संयंत्र अन्य समाजों के लिए प्रेरणास्पद बनेगा। वैसे भी मराठी समाज अन्य समाजों



की तुलना में 10–20 साल आगे चल रहा है, इसीलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र मंडल की तरह यहां के सदस्य भी अपने घरों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आम लोगों को प्रेरित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिजली बनाने के लिए खर्च होने वाले कोयले से कार्बन डाईआक्साइड निकलता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और ओजोन लेयर कमजोर होती है। अब यूरोपीय देशों सहित अमेरिका भी सौर ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर है और यह माना जा रहा है कि

आगामी 25 सालों में पूरे विश्व में जरूरत की ऊर्जा का लगभग 40 प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा प्लांट से मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में तेजी से काम करते हुए सौर ऊर्जा की योजना को पूरे देश में लागू कर चुके हैं। हमें इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

डॉ. रमन सिंह ने मंडल के प्रकल्पों की चर्चा करते हुए कहा कि कई दशकों से जिस तरह समाजसेवा के यह कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि भविष्य

हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन, सीएम साय ने केंद्र का जताया आभार

■ कहा- सरकार को युवाओं की चिंता

रायपुर। केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार का आभार जताया है।

सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं की चिंता की है। पेपर लीक के लिए कठोर कानून बना रहे हैं, जिसके बाद इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी।

बता दें कि पीएम मोदी ने 26 जुलाई को घोषणा की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन



किया गया है। इस मल्टीडिस्प्लिनरी टास्क फोर्स की अध्यक्षता देश के जाने-माने टेक्नोलॉजि एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि करेंगे।

टास्क फोर्स में तकनीक, शिक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस उच्च स्तरीय समूह में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक

वी. कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

यह टास्क फोर्स विशेष रूप से परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और संरचनात्मक सुधारों के लिए सुझाव देगी। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना और छात्रों के बीच परीक्षाओं की विश्वसनीयता कायम करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर आने वाली परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर का विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस का मिला समर्थन

प्रदेशभर के मीटर रीडरों ने सीएसईबी मुख्यालय का किया घेराव



रायपुर। प्रदेशभर में आज बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ओर कांग्रेस का सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन जारी है। दूसरी ओर बिजली मीटर रीडरों ने भी राजधानी में मोर्चा खोल दिया है। विद्युत मीटर रीडर श्रमिक संघ के बैनर तले प्रदेशभर से मीटर रीडर सोमवार को सीएसईबी मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। डडसेना भवन में मीटर रीडरों के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। दरअसल, प्रदेशभर में स्मार्ट बिजली व्यवस्था लागू होने से वर्षों से कार्यरत मीटर रीडरों के आगे आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। कई जिलों में महीनों से मानदेय भुगतान लंबित है। अलग-अलग दरों से भुगतान किए जाने के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोह है।

मीटर रीडरों का कहना है कि स्मार्ट मीटर

■ मैदानी इलाकों में जमकर बरसे बदरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन में बारिश का असमान वितरण देखने को मिल रहा है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ब्यूरो द्वारा 27 जुलाई की स्थिति में जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 1 जून से अब तक औसतन 421 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

आम उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू नहीं

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, विशेषकर इंस्टाग्राम पर 1 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू किए जाने संबंधी एक भ्रामक एवं तथ्यहीन पोस्ट प्रसारित की जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह गलत है।

वास्तविक स्थिति यह है कि प्रीपेड व्यवस्था केवल सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों पर लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। आम घरेलू, व्यावसायिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के कार्यालय उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) से जारी विज्ञप्ति में आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा बिजली संबंधी किसी भी जानकारी के लिए केवल अधिकृत एवं आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

पीएम मोदी के टास्क फोर्स गठन पर दीपक बैज ने कहा– जनाधार खो चुके हैं, इसलिए कर रहे बैलेंस

रायपुर। प्रधानमंत्री द्वारा टास्क फोर्स के गठन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स का गठन करने से क्या फायदा होगा, आपने तो पूरे देश के युवाओं का कैरियर खराब कर दिया। वे सड़कों पर हैं। इस भ्रष्टाचार को सिस्टम में बैठे लोग कर रहे हैं। युवाओं और किसानों को सड़कों पर लाने का इन लोगों की धारणा बन गई है। Gen– 5 ने प्रधानमंत्री को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया है। मोदी ने 12 सालों में देश को बर्बाद कर दिया है, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती।

बैज ने कहा, टास्क फोर्स का गठन केवल अपना जनाधार खो चुके हैं उसे बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अपने मंत्रियों को रील बनाकर पोस्ट करने की नसीहत देने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, इससे समझा जा सकता है कि एक शंखनाथ से पूरी सरकार की सिस्टम हिल चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार हिल गई है, डर चुकी है। Gen–5 को टारगेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के 65 प्रतिशत हिस्सा है। Gen–5 देश के पढ़े लिखे लोग अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, रील बनाकर डालने से क्या होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती



शुरू हो गई है, उन्हें झोला उठाकर जाना होगा।

दिल्ली में 29 जुलाई को होने वाली कांग्रेस की बैठक को लेकर दीपक बैज ने कहा, 29 तारीख को दिल्ली में सभी प्रदेश संगठनों को लेकर बैठक होने वाली है। संगठन को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। संगठन की मजबूती को लेकर दिशा निर्देश मिलेंगे। इतने दिनों में किस तरह के आंदोलन किए हैं, इन सभी की रूपरेखा तैयार की गई है। बारिश के बाद जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की रूपरेखा तैयार हो चुकी है।

प्रदेश में अब तक औसतन 421 मि.मी. वर्षा दर्ज, प्रदेश में अब तक 85 प्रतिशत बारिश



प्रतिशत), सक्ती (113.7 प्रतिशत) और राजधानी रायपुर (111.1 प्रतिशत) में भी सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे यहाँ के नदी-नाले उफान पर हैं और खेती-किसानी के काम में तेजी आई है। इसके अलावा बिलासपुर (102.5 प्रतिशत), दुर्ग (105.1प्रतिशत) और मुंगेली (100.6 प्रतिशत) में भी वर्षा का कोटा लगभग पूरा हो चुका है।

दूसरी ओर बस्तर संभाग का बीजापुर जिला राज्य में सबसे पीछे है, जहाँ अब तक महज 42.9 प्रतिशत (387.5 मि.मी.) बारिश हो पाई है। कमोबेश यही स्थिति सुकमा (45.0 प्रतिशत), मोहला-मानपुर-अंबागढ़ (114.0

चौकी) (51.8 प्रतिशत), कांकेर (54.0 प्रतिशत), कोण्डागढ़ (54.4 प्रतिशत), बस्तर (54.5 प्रतिशत) और सरगुजा (69.0प्रतिशत) जिलों की भी है, जहाँ बारिश का आंकड़ा सामान्य के आधे के आसपास ही अटका हुआ है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में औसतन 7.6 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है, जिसमें महासमुंद में सर्वाधिक 37.4 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 34.4 मि.मी. और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 33.4 मि.मी. वर्षा हुई। वहीं बलरामपुर, कोरिया, मोहला-मानपुर, बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर और देतेवाड़ा जैसे जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी है।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक चानू व रजत पदक विजेता राजा व रिशिकांता को दी बधाई

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू, पुरुष 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी व पुरुष 60 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने पर रिशिकांता सिंह चानबम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश के लिए गर्व और गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू की अटूट मेहनत,



अनुशासन, समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति ने एक बार फिर विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन देश के युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि मीराबाई चानू की यह सफलता भारतीय खेल जगत की बढ़ती ताकत और खिलाड़ियों के अथक प्रयासों का प्रमाण है।

उन्होंने इस शानदार उपलब्धि के लिए मीराबाई चानू को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अनंत शुभकामनाएं दीं।

इसी तरह वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राजा मुथुपांडी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प के बल पर

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर राजा मुथुपांडी ने यह सिद्ध किया है कि भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और समर्पण के दम पर विश्व स्तर पर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उनकी सफलता देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। राजा मुथुपांडी को इस शानदार उपलब्धि के लिए पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे आगे भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करते रहेंगे।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष 60 किलोग्राम भारोत्तोलन

स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने पर रिशिकांता सिंह चानबम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का विषय है। रिशिकांता सिंह चानबम ने अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में जीता गया प्रत्येक पदक भारत की प्रतिभा, समर्पण और खेल भावना का प्रतीक है। रिशिकांता सिंह चानबम की यह सफलता देशभर के युवा खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पूरा देश इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है।

प्रधान का नुकसान क्या राहुल का फायदा है?

प्रभु चावला

राजनीतिक आंदोलनों ने अक्सर सरकारों की दिशा बदल दी है। कुछ आंदोलनों ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, कुछ ने नीतियों में उलटफेर किया है और कुछ ने शक्तिशाली सरकारों को जन्ता के गुस्से को शांत करने के लिए मंत्रियों की बलि देने पर मजबूर किया है। यही कुछ इस सप्ताहांत नई दिल्ली में देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल से कहीं अधिक है। यह 12 वर्षों में पहली बार है कि निरंतर जन आंदोलन, जिसे विपक्ष के लगातार दबाव से बल मिला, नरेंद्र मोदी सरकार में किसी कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे का कारण बना। जैसी कि उम्मीद थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे को ‘भारत के युवाओं की जीत’ बताया। भाजपा ने इस व्याख्या को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के व्यापक हित में काम किया है। इन परस्पर विरोधी राजनीतिक बयानों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है-क्या यह इस्तीफा एक अलग-थलग रियायत है, या इसने मोदी सरकार द्वारा एक दशक से सावधानीपूर्वक बनाए गए राजनीतिक अजेयता के आभास को परास्त कर दिया है? या इसने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले हतोत्साहित विपक्ष को फिर से सक्रिय कर दिया है? दिल्ली की भीषण गर्मी में, राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड़ा के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर पालथी मारकर धरने पर बैठे थे, जबकि जंतर-मंतर से, जो उनसे बस एक किलोमीटर दूर था, ‘प्रधान हटाओ’ के नारे गुंज रहे थे। हफ्तों से यहीं दृश्य दोहराया जा रहा था-कोविंग सेंटर के छात्रों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, संसद के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा था और विपक्षी नेताओं का एक समूह बारी-बारी से माइक पर आकर नीट-यूजी पेपर लीक कांड को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। शनिवार को यह मांग पूरी हुई। एक ऐसी सरकार के लिए जिसने 12 साल तक कभी पीछे न हटने की कला में महारत हासिल की थी, यह एक दुर्लभ और शर्मनाक कदम था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, यू.पी.ए. के 10 साल के कार्यकाल में लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने इसी तरह के दबाव में इस्तीफा दिया था। एक इस्तीफे से 12 वर्षों का चुनावी वर्चस्व खत्म नहीं हो जाता और सरकार का अपना तर्क इसके विपरीत एक अलग कहानी पेश करता है—प्रधान ने अपने शब्दों में ‘छात्रों के व्यापक हित में’ इस्तीफा दिया, न कि किसी अपराध को स्वीकार करते हुए। मोदी ने परीक्षा प्रणाली में किसी भी गहरी व्यवस्थागत विफलता को स्वीकार नहीं किया है। सी.बी.आई. की मौजूदा जांच, रह हुई परीक्षा और दोबारा परीक्षा, खबरों के शांत होने के बाद शायद सरकार की हार मानने की भाजपा निर्णायक कदम के रूप में सामने आ सकती है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने इससे कहीं बड़े विवादों का सामना बिना झुके किया है और एक इस्तीफा, चाहे वह कितना भी प्रतीकात्मक क्यों न हो, राष्ट्रीय विपक्ष को पुनर्जीवित करने का कमजोर आधार है। मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और भाजपा की संगठनात्मक क्षमता, ज्यादातर मामलों में, काफी हद तक बरकरार है। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषक इस क्षण को मात्र प्रतीकात्मक नहीं मान रहे। राहुल गांधी के उस करियर में यह पहली ठोस जीत है, जो नारों से अधिक परिणामों से परिभाषित हुआ है। कांग्रेस रणनीतिकारों के लिए सबक यह है कि शिकायत की राजनीति, जब मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले किसी मुद्दे, जैसे धांधली वाली परीक्षा, छीना गया भविष्य, के साथ जोड़ दी जाए, तो यह अनूथा प्रभावशाली भाजपा के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती है। क्या यह आगामी राज्य चुनावों में कारगर साबित होगी?

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे....)

पुराणों में जिन जद, नदी, सरोवरों, पर्वतों किंवा नगरों का जहाँ-जैसा जिसतरह का वर्णन किया गया है वे सब मुख्यतया सूक्ष्म जगत् में उसी रूप में और उसी परिमाण में ठीक ठीक वैसे ही विद्यमान हैं। साथ ही गौणरूपेण इस स्थूल जगत् में भी तत्तत् पदार्थों के प्रतिनिधिभूत नद, नदी, सरोवर और पर्वतादिक विद्यमान तो अवश्य हैं परन्तु उनमें पुराणणित सब गुण अथवा अवगुण घटित होते हों सो बात नहीं है। जिस तरह कामाज पर बने हुवे भूगोल-चित्र में किंवा गारा, मिट्टी, मोम और मसाले से तैयार किये हुवे भूपिण्ड में हमारे इस दृश्य संसार के प्रायः सभी प्रधान 2 नद, नदी, सरोवरों, पर्वतों और नगरों के रूप-रेखात्मक चिन्ह तो अवश्य विद्यमान होंगे परन्तु नाप तोल परिमाण में और करणभूत सामग्री में वे बनावटी चित्र वास्तविक भूपिंड नहीं हो सकते, ठीक इसीप्रकार हमारा स्थूल जगत् भी उस इन्द्रियातीत सूक्ष्म जगत् का

प्रतिचित्र: नक्शा मात्र है। इस स्थूल जगत् के समस्त नद, नदी, सरोनबादिक उस सूक्ष्म जगत के नद, नदी आदि पदार्थों के ही निदर्शनमात्र है। नक्शे की नीली रेखाएं जिस तरह गङ्गा, यमुना आदि नदियों की प्रतिमूर्ति होती हुई भी असली नदियों की भांति अपनी उताल तरङ्गों से किनारों को प्राप्तातिव नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह सूक्ष्म जगत् के पदार्थों के प्रतिकृतिभूत स्थूल-जगत्-संस्थित नद, सरोवरादिक भी अपनी सीमा तक ही पुराणवर्णित भूगोल के साथ समता रखते हैं। इसलिये पौराणिक भूगोल का अध्ययन करते हुवे पाठकों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि इस प्रसंग में जिन 2 पदार्थों का जैसा संस्थान पुराणों में अङ्कित है वह सोलहों आने तो सूक्ष्म जगत में ही उपलब्ध हो सकता है उसकी प्रत्याकृतिमात्र हमारे इस स्थूल जगत् में मिल सकती है, यही पौराणिक-भूगोल शैली की विशेषता का रहस्य है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

मोदी के सेल्फी वीडियो संवाद के सियासी मायने

कमलेश पांडे

जब नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र राजनीति गरमाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर किए अपने एक लगभग 2.55 मिनट के सेल्फी वीडियो पोस्ट के माध्यम से जेन-जी से संवाद स्थापित कर विपक्षी नेताओं के सियासी चक्रव्यूह को सफलतापूर्वक भेद दिया। छात्र आंदोलन के दृष्टिगत प्रधानमंत्री के सेल्फी वीडियो संवाद के नीतिगत व सियासी मायने दूरगामी प्रभाव वाले साबित होंगे।

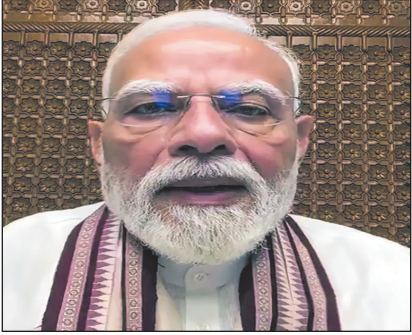
इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णायक पहल से पुनः यह स्पष्ट हो गया कि पीएम मोदी भारतीय राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं और जब जब सियासी फूटबॉल सुर्खियों में आता है, तब तब वह खुद ही आगे आकर कांग्रेस के नेता सिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक मैदान का तगड़ा गोल मारते हुए उन्हें अप्रसंगिक बना डालते हैं। बोते 12 वर्षों में ऐसे कई मौके आए जब भाजपा का विकल्प बनने चला कांग्रेस नीत विपक्ष अपने संकल्प सिद्धि की राह से ही भटक गया या प्रधानमंत्री की नीतिगत पहल से भटका दिया गया, राजनीतिक शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान का विषय है।

बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई दिन गुरुवार की मध्य रात अपनी एक सेल्फी-स्टाइल वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसका केंद्र बिंदु NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसा संवेदनशील मुद्दा था। उस वीडियो में पीएम मोदी ने भवुकता भरे अंदाज में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कहीं।

पहला, उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों को गहरा दुख और मानसिक पीड़ा होती है।

दूसरा, उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और पेपर लीक रोकने के लिए व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।

तीसरा, उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक ऐसे विधेयक पर विचार करेगा, जिसमें पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का प्रावधान, दोषियों के लिए कड़े दंड, और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय शामिल हों। चौथा और अंतिम, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता



रही कि पेपर लीक के कारण छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।

देखा जाए तो यह वीडियो इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे रात लगभग 11:52 बजे, अपेक्षाकृत अनौपचारिक सेल्फी वीडियो के रूप में जारी किया, जिसे कई विश्लेषकों ने युवाओं, विशेषकर Gen-Z, से सीधे संवाद स्थापित करने की नई शैली के रूप में देखा। बाद में, उन्होंने दूसरे वीडियो में युवाओं को उनकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे इंस्टाग्राम वीडियो में मुख्य रूप से युवाओं, खासकर छात्रों, को संबोधित किया। उनके संदेश का सार यह था कि पिछले वीडियो पर युवाओं की प्रतिक्रिया और सकारात्मक सुझावों के लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा, "Thank you, friends. कल देर रात आपसे जुड़ने का अवसर मिला। आपने मेरे वीडियो पर जिस तरह प्रतिक्रिया दी और सकारात्मक सुझाव दिए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं का यह स्नेह और सुझाव सरकार के प्रयासों को और मजबूत करेंगे तथा उनका युवाओं से जुड़ाव और गहरा होगा।

दरअसल, वह वीडियो उनके उस पहले इंस्टाग्राम संदेश के बाद आया, जिसमें उन्होंने हृद्यश्रृङ्ख सहित परीक्षा-पत्र लीक के मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई, सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक अदालतों की बात कही थी। दूसरे वीडियो का उद्देश्य उस पहले संदेश पर मिली प्रतिक्रिया के लिए युवाओं का आभार व्यक्त करना था। राजनीतिक दृष्टि से, कई विश्लेषकों ने इसे Gen-Z युवाओं से सीधे डिजिटल संवाद स्थापित करने की रणनीति के रूप में देखा है, जबकि विपक्ष ने इसकी आलोचना भी की है। यदि बात उसी इंस्टाग्राम वीडियो और उसके बाद की घटनाओं की है, तो यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि छात्र

आंदोलन पर उसका निर्णायक प्रभाव पड़ा है।

अब तक मिली जानकारी के आधार पर कुछ संभावित प्रभाव दिखे हैं-जैसे आंदोलन की दिशा बदली, समाप्त नहीं हुई। हां, प्रधानमंत्री द्वारा सीधे छात्रों को संबोधित करने और पेपर लीक पर सख्त कानून तथा फास्ट-ट्रैक अदालतों की बात करने के बाद आंदोलन का फोकस केवल विरोध से हटकर सरकार के वादों के क्रिया-व्ययन पर भी आ गया। वहीं कुछ छात्रों में इसका सकारात्मक संदेश गया। कई छात्रों ने इसे इस संकेत के रूप में देखा कि सरकार ने उनकी चिंता को गंभीरता से लिया है और शीघ्र स्तर से प्रतिक्रिया आई है। वहीं कुछ छात्रों में संदेह भी बना रहा।

खासकर छात्र संगठनों और विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा कि केवल घोषणा पर्याप्त नहीं है; वास्तविक बदलाव तब माना जाएगा जब पेपर लीक के मामलों में शीघ्र कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले, और परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार दिखाई दें। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

लिहाजा सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई। वीडियो के बाद #PaperLeak, #NEET और युवाओं से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इससे मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में बना रहा। जहाँ तक समय आकलन की बात है तो इस समय उपलब्ध संकेतों के अनुसार, प्रधानमंत्री के संदेश ने राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव अवश्य डाला है, लेकिन क्या इससे छात्र आंदोलन स्थायी रूप से कमजोर पड़ा या समाप्त हो गया, ऐसा कहना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित नहीं होगा। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार अपनी घोषित कार्रवायों को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से लागू करती है, और छात्र संगठन उन कदमों को कितना पर्याप्त मानते हैं। हालांकि, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर मध्य रात्रि में विशेष रूप से Gen-Z (जेन-जी) युवाओं को संबोधित किया गया, उसके कई राजनीतिक, प्रशासनिक और संचार-संबंधी मायने हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

पहला, डिजिटल पीढ़ी तक सीधे पहुंचने की रणनीति: Gen-Z पारंपरिक मीडिया की तुलना में सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय है। देर रात भी इस आयु वर्ग का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन रहता है, इसलिए उस समय संदेश देना अधिक प्रभावी माना जा सकता है।

दूसरा, भविष्य के मतदाताओं पर फोकस: 18-29 वर्ष के लगभग 50 करोड़ युवा मतदाता

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस



भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि इस तरह की समस्याओं के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडा रहे हैं और हमें यह भली-भांति जान लेना चाहिए कि इन प्रजातियों के लुप्त होने का सीधा असर समस्त मानव सभ्यता पर पड़ना अवश्यम्भावी है।

पहले जान लें कि प्रकृति है क्या? पर्यावरण पर प्रकाशित ‘प्रदूषण मुक्त सांस’ पुस्तक में बताया गया है कि प्रकृति के तीन प्रमुख तत्व हैं जल, जंगल और जमीन, जिनके बगैर प्रकृति अधूरी है और यह अनभिज्ञ हो और हमें यह स्वीकार करने से

तत्वों का इस कदर दोहन किया जा रहा है कि इसका संतुलन डगमगाने लगा है, जिसकी परिणति अक्सर भयावह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने भी आने लगी है। प्राकृतिक साधनों के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही नतीजा है कि पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, जंगल, वन्य जीव और वनस्पति, इन सभी का संरक्षण अत्यावश्यक है। दुनियाभर में पानी की कमी के गहराते संकट की बात हो या ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के तपने की अथवा धरती से एक-एक कर वनस्पतियों या जीव-जंतुओं की अनेक

प्रजातियों के लुप्त होने की, इस तरह की समस्याओं के लिए केवल सरकारों का मुंह ताकते रहने से ही हमें कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि प्रकृति संरक्षण के लिए हम सभी को अपने-अपने स्तर पर अपना योगदान देना होगा। प्रकृति के साथ हम बड़े पैमाने पर जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय से भयानक तुफानों, बाढ़, सूखा, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ा है।

पर्यावरण का संतुलन डगमगाने के चलते लोग अब तरह-तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनकी कार्यक्षमता भी इससे प्रभावित हो रही है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज पर ही खर्च हो जाता है।

आज का इतिहास

- 1957 जापान के इशहाया में भारी बारिश की वजह से 992 लोगों की मौत हुई।
- 1959 ग्रेट ब्रिटेन में डाक कोड का प्रयोग शुरू हुआ।
- 1976 रिक्टर पैमाने पर कम से कम 8.2 तीव्रता का भूकंप, जो इतिहास में सबसे घातक है, चीन के तांशानान में फैल गया, जिसमें कम से कम 2,40,000 लोग मारे गए।
- 1977 ट्रांस-अलास्का पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से पहला तेल बाल्डेज, अलास्का पहुंचा।
- 1978 सोवियत संघ ने पूर्वोत्तर कजाखस्तान में परमाणु परीक्षण किया।
- 1983 नासा ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह टेलस्टार-3ए का प्रक्षेपण किया।
- 1989 ब्रेक्स डेल मर्फ़ी ने एक पारी में 2 3 रन की घरेलू पारी खेली। वह एक पारी में 2 घरेलू रन बनाने वाले 14 वें व्यक्ति हैं। उन्होंने एक पारी में 6 आरबीआई का रिकॉर्ड भी बनाया है।
- 1990 अल्बर्टो फुजिमोरी पेरू के राष्ट्रपति बने।
- 1995 संयुक्त राज्य अमेरिका के अटार्नी की डिस्ट्रिक्ट अरिगॉन की हत्या के लिए भगवान श्री रजनीश के दो अनुयायियों को दोषी ठहराया गया था।
- 1996 प्रागैतिहासिक केनेविक मैन के अवशेषों की खोज अमेरिका के वाशिंगटन, केनेविक के पास कोलंबिया नदी के ओना बैंक में की गई थी।
- 1998 लेव्स्की और स्टार ने लेव्स्की और उसके माता-पिता के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा समझौते की घोषणा की। इसे महीनों के सत्ता संघर्ष के बाद बनाया गया था।
- 2005 अंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए निरंकुश आयरलैंड बनाने के लिए अपने अभियान को समाप्त करने की घोषणा की।
- 2010 कैलिफोर्निया के गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेज़ ने वित्तीय स्थिति में आपदाग्रस्त का जवाब दिया है। उसने अधिकारिता राज्य कमचारियों को प्रति माह तीन दिन की अवैतनिक छुट्टी लेने की आवश्यकता का जवाब दिया।
- 2011 अमेरिका के तैराक रयान लोच्टे ने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने शंघाई, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित 2011 वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
- 2011 एक ट्रोजन क्षुद्रग्रह जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान परिक्रमा करता है, खगोलविदों द्वारा पहचाना जाता है। खगोलविदों ने कहा कि यह पृथ्वी के लिए एक खतरा है क्योंकि यह एक गुरुत्वाकर्षण मीठे स्थान में बैठता है।

फिर युवाओं को नया मोहरा बनाती राजनीति

अमिताभ श्रीवास्तव

देश में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा(नीट) के पेपर लीक घोटाले को लेकर हंगामे का विस्तार लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर-मंतर से आरंभ धरना-प्रदर्शन 20 जुलाई को संसद के द्वार तक पहुंच गया। सुरक्षा व्यवस्था के चलते एक सीमा को लांचने की कोशिश हुई तो संघर्ष हिंसक हो उठा और पथराव से लेकर लाठीचार्ज तक सब कुछ हुआ। चूंकि संसद का सत्र आरंभ हो चुका था, इसलिए राजनेताओं का राजधानी दिल्ली में जमावड़ा स्वाभाविक था। लिहाजा युवाओं के प्रति सहानुभूति से लेकर पुलिस बर्बरता पर आंदोलन खड़ा हो गया।

सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के सहारे उसे गांव-गांव पहुंचने में सहायता मिल गई। कहीं न कहीं विद्यार्थियों के आक्रोश को राष्ट्रीय स्वरूप मिलना आरंभ हो गया। किंतु केंद्र सरकार ने अपनी गति या फिर किसी चिंता में अचानक कदम उठाने का प्रयास नहीं किया। जिससे साफ हुआ कि सरकार राजनीति और छात्र-छात्राओं की समस्याओं को अलग-अलग निपटाना चाहती है।

इस्तीफे से आगे: क्या मिल सकेगी समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की वास्तविक गारंटी?



ज्योति भास्कर

यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक प्रकरण से उपजे छात्रों के व्यापक आक्रोश और उस पर सवार राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुख्यतः राजनीतिक मजबूरी का परिणाम है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश की परीक्षा प्रणाली को वर्षों से खोखला कर रही प्रश्नपत्र लीक की संस्थागत बीमारी के उपचार और समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा।

दरअसल, पेपर लीक की समस्या किसी एक परीक्षा, एक एजेंसी या एक सरकार तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ दशकों में तकरीबन हर बड़े राज्य में कभी शिक्षक भर्ती, कभी पुलिस भर्ती, कभी राज्य लोक सेवा आयोग और कभी मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे हैं। अर्थ स्पष्ट है कि संकट उस संस्थागत ढांचे का है, जिसकी सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही लगातार कमजोर हुई है। सरकारें बदलती रही हैं, मंत्री बदलते रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा है।

ऐसे में, किसी एक मंत्री का इस्तीफा राजनीतिक जवाबदेही का प्रतीक तो हो सकता है, लेकिन इससे व्यवस्था बदलेगी ही, यह निश्चित तौर पर कह पाना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र से पहले ही

इसी बीच, कुछ दलों की इच्छा युवाओं की आड़ में अपना उल्टू सीधा करने की भी दिखी। जिसे सबसे पहले युवाओं की ओर से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने भांप लिया। उन्होंने राजनीतिज्ञों का सहयोग जंतर-मंतर पर मांगा और प्रधानमंत्री आवास के समक्ष अलग धरने को विद्यार्थियों के प्रति गंभीरता में कमी बता दिया।

वैसे यह मामला देश के पक्ष और विपक्ष का था, मगर परेशानी का समाधान निकालने से अधिक पहचान को उभारने का यह अवसर युवाओं को रिझाने अथवा दल विशेष के प्रति नफरत पैदा करने का था। दरअसल यही अवसरों की तलाश में रहने वाली राजनीति फिलहाल युवाओं के माध्यम से अपना भविष्य देख रही है और चुनौतियों का समाधान नहीं निकाल रही है।

ताजा शिक्षा का संदर्भ एक प्रवेश परीक्षा से लिया जाए तो देश भर में चिकित्सा क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम के सर्वाधिक महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि सबसे अधिक 15,395 सीटें कर्नाटक में हैं। महाराष्ट्र दोनों ही मामलों में तीसरे और चौथे स्थान पर है। देश



में चिकित्सा शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रम एमबीबीएस की कुल 1,36,939 सीटें हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज 823 हैं।

महाराष्ट्र में एमबीबीएस पाठ््यक्रम की 13,099 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 14,000 है। यदि आंकड़ों की नजर से देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में संबंधित राज्यों में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। प्रवेश प्रक्रिया के हिसाब से ‘नीट’ प्रतिस्पर्धा परीक्षा है। जिसमें प्रावीण्यता सूची और प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश मिलता है।

इस दृष्टिकोण से विद्यार्थियों का प्रवेश

योग्यता आधारित हो जाता है। जिसके लिए प्रयास स्पष्ट रूप से कम दिखाई देते हैं। ‘नीट’ परीक्षा घोटाले के प्रदर्शन के बीच हुई दूसरी बार परीक्षा में अनेक विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन को सुधारा और अच्छा स्थान प्राप्त किया। जिससे योग्यता को मिले बल से परिणामों में परिवर्तन सिद्ध हुआ।

परीक्षा की गड़बड़ी को कोस कर सीमाओं में बंधे रहना निरर्थक साबित हुआ। मगर हंगामे के बीच विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर चर्चा नहीं हुई। कठिन समय में परीक्षा में सफलता पाने वालों की पीठ थपथपाई नहीं गई। सफल विद्यार्थियों को नए छात्र-छात्राओं के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।

दो माह की अवधि में केवल युवाओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए उपयोग में लाने का प्रयास किया गया। जंतर-मंतर पर युवा करीब 19 दिन से ‘नीट’ परीक्षा के घोटाले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनसे जुड़ी कॉकरोच जनता पार्टी (सोजेपी) ने नई दिल्ली में 20 जून से आंदोलन शुरू किया था। जिसकी मांग प्रतियोगी परीक्षाओं में

नैतिकता नहीं, भारी युवा आक्रोश के चलते हुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

तनवीर जाफ़री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों व युवाओं का आंदोलन अभी लगभग पूरे देश में फैलता ही जा रहा था कि गत शनिवार सरकार को उन्हें पद से हटाना ही पड़ गया। आंदोलित छात्रों को केवल विपक्ष या अन्य तमाम सेलेब्रिटीज् का ही समर्थन नहीं मिला बल्कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी का भी समर्थन हासिल हुआ। जोशी ने छात्र आंदोलन को अपना समर्थन देते हुये कहा था कि महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों के साथ बेरहमी से बुरा व्यवहार किया गया, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर हैं और उनकी चिंताएँ वाज्य हैं, जिनका समाधान सहानुभूति और संवाद के माध्यम से होना चाहिए था, न कि केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानकर बल प्रयोग से। परन्तु अहंकारी सत्ता ने समय रहते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की उनकी मांग पूरी करने के बजाय पुलिस बल का प्रयोग कर उन्हें भयभीत करने की रणनीति अपनाई। और आखिरकार पुलिस की दमनकारी नीति सरकार को और भारी पड़ गयी।

सवाल यह है कि जिस धर्मेंद्र प्रधान के जुलाई 2021 से जुलाई 2026 तक के शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान देश में अलग-अलग स्तरों पर लगभग 70 से 80 बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। जिस धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री मंत्री रहते विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (विशेषकर NEET और UGC-NET) में हुई पेपर लीक की घटनाओं और उनके मानसिक तनाव के कारण और उसके बाद उनके भविष्य को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता के चलते पिछले कुछ हफ्तों में ही 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। और देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित हुआ, केवल नीट परीक्षा के पेपर लीक, परिणाम रद्द होने और री-टेस्ट के कारण अकेले 22 लाख से अधिक (2.2 मिलियन) छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया और उन्हें दोबारा भीषण मानसिक तनाव में परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी। इसी तरह यूजीसी-नेट परीक्षा, डार्क नेट पर पेपर लीक होने की बजह से रातों-रात परीक्षा रद्द होने के कारण 9 लाख से अधिक छात्रों का कैरियर सीधे



प्रभावित हुआ। ऐसे शिक्षा मंत्री को हटाने में सरकार को आखिर इतना समय क्यों लगा ?

दरअसल धर्मेंद्र प्रधान बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों से गहराई से जुड़े रहे हैं। उनका पूरा राजनीतिक और सामाजिक आधार संघ से ही प्रेरित रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉ. देबेंद्र प्रधान ओडिशा में भाजपा के शुक्रआती नेताओं में से थे और स्वयं संघ के आजीवन कार्यकर्ता रहे। डॉ. देबेंद्र प्रधान 1998-2004 के मध्य वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। जुलाई 2021 में जब धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान उन्होंने पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा कर भारतीय महापुरुषों और स्वदेशी इतिहास को प्रमुखता से शामिल करने का कार्य किया, जिसे संघ के सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुकूल माना जाता है।

धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और नए नेशनल Curriculum फ़्रेम वर्क (NCF-SE 2023) के तहत स्कूली पाठ्यक्रमों (विशेषकर NCERT किताबों) में व्यापक बदलाव किए गए। इसमें वेदों, प्राचीन भारतीय ग्रंथों, पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन खगोल विज्ञान और भारत की समृद्ध गणितीय विरासत (जैसे प्राचीन गणितज्ञों के योगदान) से जुड़े संदर्भों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कक्षा 6 से ही कोडिंग, वित्तीय साक्षरता,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और स्थानीय शिल्पकला (जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बागबानी आदि) जैसे व्यावहारिक विषयों को मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा गया।

जंतर-मंतर से उठी नई आवाज : जब जेन-जी ने बदल दी राजनीति की भाषा

सौरभ जैन अंकित

ऑल इज् वेल केवल एक फिल्मी संवाद नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी की उम्मीदों का प्रतीक बन गया था। फिल्म 3 इंडियन्स में शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ जो संदेश दिया गया था, वही सवाल आज वास्तविक जीवन में फिर गूँज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब पर्दे का काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और देशभर के हजारों युवा जंतर-मंतर से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं ने देश के लाखों छात्रों के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। वर्षों की कठिन मेहनत, आर्थिक संघर्ष और भविष्य के सपनों के बीच यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे, तो यह केवल एक परीक्षा का संकट नहीं रह जाता, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न बन जाता है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। यह आंदोलन युवाओं की उस व्यापक बेचैनी का प्रतीक बन गया, जिसमें रोजगार, अवसरों की समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे शामिल हैं। आज की जेन ज़ी केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि वह तथ्यों, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों की मांग करती है। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी रही कि इसमें किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं दिखाई दिया। छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग लेकर सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को नई ताकत दी। एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मंचों पर युवाओं ने अपनी बात सीधे देश तक पहुंचाई। पारंपरिक मीडिया से इतर डिजिटल प्लेटफॉर्म इस आंदोलन का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरे। यही कारण है कि यह आंदोलन राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सतारूद्ध भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती केवल परीक्षा सुधार की नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की भी है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून, फास्ट ट्रैक अदालतों और दोषियों

चुनौतियों को देखते हुए भी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं को सुगम बनाने के लिए अधिक कारगर उपाय नहीं हुए हैं।

हमेशा हर परीक्षा की नुटितविहीन मानकर आयोजित किया जाता है, लेकिन उस दावे की पोल-खोल में अधिक समय नहीं लगता है। किंतु किसी भी सरकार अथवा राजनीतिक दल की ओर से परीक्षा पद्धति में ठोस सुधार के लिए अलग पहल नहीं की जाती है। वर्तमान केंद्र सरकार ने अनेक परीक्षा संस्थाओं को गठित किया है, लेकिन उनके पास व्यवस्थित आयोजन से आगे संभावित गड़बड़ियों से निपटने की कोई योजना नहीं है। वे एक बार गिरने के बाद दोबारा न गिरने पर विचार करती हैं। यही जानते हुए राजनीतिक दल समस्याओं से निपटने से अधिक युवाओं में अपना लाभ देखते हैं। दूसरी और भविष्य की चिंता में युवा कभी इस पाले तो कभी उस पाले में मोहरे बनकर नजर आते हैं। दोनों के बीच सरकार और उसकी व्यवस्था निश्चित बनी रहती है। आवश्यकता युवाओं के मन में निश्चिंता का भाव लाने की है, जिसे कोरी बातों या राजनीतिक दांव-पेंच से नहीं लाया जा सकता है।

स्कूली स्तर पर स्वास्थ्य, कल्याण और योग को शारीरिक शिक्षा के अनिवार्य और मुख्य मूल्यांकन का हिस्सा बनाया गया। इसी तरह हृष्टश्रक्क की कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबों से पाठ्यक्रम का लगभग 30% हिस्सा हटा दिया गया, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। इतिहास की किताबों (विशेषकर कक्षा 12वीं) से मुग़ल दरबार, मुग़ल शासकों के इतिहास और उनके प्रशासनिक तौर-तरीकों से जुड़े कुछ विस्तृत अध्यायों और अंशों को हटाया या छोटा किया गया। सामाजिक विज्ञान की किताबों से 2002 के गुजरात दंगे, देश में लागू हुआ आपातकाल, नक्सली आंदोलन और शीत युद्ध के दौर से जुड़े कई महत्वपूर्ण पर स्मष्टीकरण देते हुए कहा था कि यह बदलाव निष्पक्षों की राय, विभिन्न स्तरों पर पाठों के दोहराव को रोकने और छात्रों को आधुनिक समय की ज़रूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए किए गए हैं, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत। शायद यही वजह थी कि संघ के एजेंडे को लागू करने वाली नई शिक्षा नीति के कार्यान्वन के मध्य सरकार प्रधान को हटाना नहीं चाह रही थी। परन्तु अब राजनीतिक गलियारों में अप्रुष्ट रूप से यह चर्चा भी हो रही है कि युवा आंदोलन के मध्य संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सरकार को युवाओं के साथ संवाद और संवेदनाशीलता बरतने के दिए गए हालिया सुझाव के बाद ही सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला किया है। बहरहाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद देश भर में युवाओं में दौड़ती खुशी के लहर इस बात का सुबुत है कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के चलते नहीं बल्कि भारी युवा आक्रोश के चलते शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है जिसे देश की युवा शक्ति अपनी बड़ी सफलता और जीत के रूप में देख रही है।

छात्रों के आंदोलन का कुछ राजनेताओं ने कर दिया राजनीतिकरण!

ललित गर्ग

नीट-यूजी की 3 मई 2026 को आयोजित मूल परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों के बाद 12 मई 2026 को सरकार ने नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया था। तब से ही छात्रों में आक्रोश व्याप्त है और वह देश के विभिन्न हिस्सों में शांति पूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपना जबरदस्त विरोध प्रकट कर रहे थे। लेकिन अचानक ही 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (ष्ट्रक्क) नामक एक पार्टी बन जाती है और वह पार्टी छात्रों के आंदोलन में कूद पड़ती है, उस पार्टी के द्वारा दिल्ली में जून के प्रथम सप्ताह से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाता है, इस धरना प्रदर्शन में सबकुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन जब से कुछ राजनेताओं की एंट्री हुई है तब से ही छात्रों की मूल मांगों से खिलवाड़ होना शुरू हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के पेपर लीक के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (ष्ट्रक्कु) को इस मामले की जांच सौंपी दी थी। वही सरकार के द्वारा नए सिरे से नीट की पुनपरीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जा चुकी है, 16 जुलाई 2026 की रात को पुनपरीक्षा के नतीजे भी एनटीए के द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन आजकल जबरदस्त प्रतियोगिता के इस दौर में सरकारी नौकरी व महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर बार-बार रद्द होने के कारण देशभर से छात्रों में भारी मानसिक तनाव के चलते विरोध की स्थिति जबरदस्त ढंग से देखने को मिल रही है। छात्रों के द्वारा लगातार देश व प्रदेशों के नीति-निर्माताओं से परीक्षाओं की निष्पक्षता और छात्रों के बीच विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए धरातल पर ठोस आवश्यक कदम उठाने की मांग भी लगातार की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार निरंतर छात्रों को आश्चस्त कर रही थी कि वह भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है, फिर भी आंदोलन जारी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र आंदोलन में जब सोशल एंक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की एंट्री होती है, वह भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और जब भूख हड़ताल एक-एक दिन करके लंबी चलने लगती है, तब छात्रों का शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा यह आंदोलन देश के कुछ राजनेताओं के लिए अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए एक शानदार पर्यटन



स्थल बन जाता है, जिसके चलते धरनास्थल पर बहुत तेजी से छोटे व बड़े राजनेताओं का तांता लगने लग जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की स्थिति कुछ लोगों व राजनेताओं के द्वारा देश राजधानी दिल्ली में बनायी जा रही है, उससे अब यह स्पष्ट होता जा रहा कि लंबे अरसे से आंदोलनरत छात्रों की मूल मांगों राजनीतिकरण के चलते अब पीछे छूट गई हैं। छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को आज कुछ लोगों के गैंग ने छात्र हित के जगह पर्दे के पीछे छिपी सत्ता हथियाने की सीढ़ी से केंद्र व प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन करने का हथियार बना लिया है। छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोगों व राजनेताओं ने पूर्व की भांति ही सत्ता परिवर्तन करने की महत्वाकांक्षा का हथियार बनाते हुए आंदोलन को राजनेताओं की स्वार्थ पूर्ति अखाड़ा बनाकर रख दिया है। हर बार की ही तरह इस बार भी छात्रों के बेहद शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन को कुछ चतुर, चालाक व बेहद ही स्वार्थी राजनेता ने घुसकर के छात्रों व देश युवाओं के केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश को अपने क्षणिक हितों को साधने की ताकतवर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने व्यक्तिगत एजेंडे व हितों की पूर्ति करने व पार्टी के हितों को साधने वाली राजनीतिक जमीन को मजबूत करने वाला आंदोलन बनाकर रख दिया है। छात्रों के नाम पर शुरू हुए आंदोलन में अब छात्रों के हित की बातें बहुत पीछे छूटते जा रही हैं, राजनेताओं के छिपे हुए एजेंडे छात्र व नौजवानों के हितों पर हावी होते जा रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा आंदोलन को हिंसक बनाते हुए राजनीतिकरण किया जा रहा है।

नीट परीक्षा लीक कांड के बाद से ही सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकते हुए देश में छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए रणनीति बनाने की

कलर और कैरेक्टर का सुंदर कॉम्बिनेशन

कई बार लोग अपने घरों के इंकोरेशन को लेकर काफी सीरियस होते हैं। वे चाहते हैं कि जब भी कोई मेहमान उनके घर आए तो उनके घर का इंटीरियर देखकर दंग रह जाए। ऐसे में लोग घरों को सजाने को लेकर कई प्रयोग करते हैं, लेकिन घर को टंड में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं टंड के मौसम में घर किस तरह से सजाएं।



कलात्मकता...

कूल सीजन में कलर और कैरेक्टर को मिलाकर सुंदर सजावट का काबिनेशन बनाएं और देखिए कि रंग व आकृतियों का मिश्रण किस तरह कमरे की खूबसूरती को बढ़ा देता है वो भी तब जब आपकी कल्पनाशीलता उसे और अधिक निखार दे। इस मौसम में चटख रंग अच्छे लगते हैं। रंगों के साथ फैब्रिक्स व टेक्सटाइल्स का उपयोग सजावटी चीजों के साथ कमरे के बैकग्राउंड को और भी निखार देता है। कलात्मक तरीके से लगाई गई मूर्तिनुमा आकार के लैंप, डेलिकेट फानूस इंटीरियर की स्टाइल को सुरंर बनाते हैं।

ग्लास के प्रयोग से नया लुक

कमरे में विभिन्न कोणों से आने वाले प्रकाश के लिए जरूरी है कि कमरे के आकार, साइज, स्टाइल और रंगों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा उसी के अनुसार कमरे की हर चीज की फिटिंग व प्रेजेंटेशन हो। इस मौसम में मोटे पेटे टंड से बचाव करते हैं। बहुत अधिक फंक्शनल फिटिंग कमरे की डिजाइन को प्रभावित करती है, खासकर बाथरूम व किचन की। छोटी-बड़ी चीजों का मॉर्डन या हाईटेक या क्लासिक तरीके से किया गया डिजाइन घर को इस मौसम में विशेष खूबसूरती प्रदान करता है। सिक या किचन में टाइल्स, मार्बल्स या ग्लास का उपयोग भी एक नया लुक देती है।



जल्द अपडेट करें आईफोन...

एक मालवेयर के चलते एप्पल ने इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट पेश किया है और अगर आपने अपने आईफोन को अपडेट नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। यह मालवेयर टैक्स्ट मैसेज, ई-मेल आदि को पढ़ सकता है और कॉल रिकार्ड (क्वेट्सएप और वाइबर कॉल्स) कर सकता है। इसके साथ ही लोकेशन और आपके फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए अपने आईफोन को 9.3.5 पर अपडेट कर लें। अगर यह मालवेयर आपके आईफोन में आ गया तो हैकर के पास आपके फोन का सारा कंट्रोल होगा। इसका नाम ट्रिंडेंट है और मोबाइल सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने इसके बारे में जानकारी दी है। आईओएस 9 में यह एप्पल के सिक्योर प्लेटफार्म को ब्रेक कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सिटीजन लैब के मुताबिक ट्रिंडेंट एक स्पॉइवयर प्रोडक्ट है जिसे इंजराइल आधारित साइबर वार कम्पनी एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया है। आईफोन को अपडेट करने के लिए फोन की सेटिंग्स > जनरल > अबाउट > वर्जन में जाकर आईओएस वर्जन को चैक करें और नए वर्जन को अपडेट कर लें।

गूगल का खास फीचर...

गूगल जल्द ही अपने वाई-फाई असिस्टेंट फीचर को नैक्स फोन्स के लिए रोल आउट करने जा रही है। इस वाई-फाई असिस्टेंट फीचर की मदद के साथ यूजर्स रेंज में आने वाले कई मिलियनज ओपन और फ्री वाई-फाई होटस्पोटस को सुरक्षित तरीकों के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। इस का प्रयोग करने के लिए यूजर्स को एंड्रायड सेटिंग में जाकर गूगल पर टैप करना होगा। इस के बाद नेटवर्किंग को सेलेक्ट कर आप फीचर को स्विच कर सकते हो जिस में टर्न ऑन और टर्न आफ की आषाण दी होगी। एक बार स्विच ऑन करने पर डिवाइस के उपर वाले कोने में एक की-आइकन दिखाई देगा। यह आइकन आपको एक फ्री वाई-फाई नेटवर्क के एक कनेक्शन की सूचना देगा। फिलहाल वाई-फाई असिस्टेंट फीचर सबसे पहले यूएस, कैंनेडा, मैक्सिको, द यूके और नोरडिक देशों के नैक्सस फोन्स के लिए रोलआउट किया जा जाएगा।

घर में टीवी देखते हुए इंसान शायद ही सोचता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन ड्राइंग रूम में स्मार्ट टीवी के आने के बाद ऐसा नहीं रहा। आधुनिक स्मार्ट टीवी डाटा तो रिसीव करते ही हैं, डाटा भेजते भी हैं। इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। लोग इस खतरे को समझ नहीं रहे। चैनल इस तरह हमारे टीवी देखने की आदत का प्रोफाइल बना सकते हैं। आईटी एक्सपर्ट बताते हैं कि इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर होता है।

स्मार्ट टीवी के यूजर इसे आम टीवी जैसा सोचते हैं जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन स्मार्ट टीवी एक सक्रिय मशीन हैं, जो वह सब सुनती और देखती है, जो आप टीवी में देखते हैं या इंटरनेट पर करते हैं। बड़ा खतरा यह है कि लोग इसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। उनकी निगरानी हो रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। हर बार जब हम स्मार्ट टीवी को ऑन करते हैं या चैनल चेंज करते हैं, तो टीवी सेट उस चैनल की वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है। वहां से एक डाटा सुरक्षा गाइडलाइन मिलती है, जिसका काम इस बात का ध्यान दिलाना है कि चैनल अब डाटा कलेक्ट कर रहा है।

यह सूचना अक्सर छुपी हुई होती है। यूं भी डाटा कलेक्शन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस डाटा का इस्तेमाल जिस तरह से हो सकता है, वह अपने आप में दिलचस्प है। आईटी एक्सपर्ट बताते हैं कि इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर होता है। इस निगरानी का इस्तेमाल आपके अनुरूप विज्ञापन दिखाने के लिए हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आपके मेडिकल इंश्योरेंस की फीस बढ़ा दी जाए क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेलिविजन देखते हैं। चैनल इस तरह हमारे टीवी देखने की आदत का प्रोफाइल बना सकते हैं। यदि एक से ज्यादा लोग एक ही टेलिविजन सेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे समस्या हो सकती है। पर्सनलाइज्ड विज्ञापन इस तरह के हो सकते हैं कि यदि आप रात में ब्रूम फिल्टमें देखते हैं, तो दिन में आपके बच्चों को खास तरह के हथियारों का विज्ञापन दिखाया जाएगा।

निजता पर हमला

हम डाटा के जो निशान छोड़ते हैं, अब उनकी मदद से आजकल पर्सनेलिटी प्रोफाइल बनाए जा सकते हैं। आईटी एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे डाटा से काफी कुछ जाहिर हो जाता है। इस बात का पता किया जा सकता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्या आप भावुक है या फिर खुले मिजाज वाले। यानी पर्सनेलिटी के जो पांच प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनसे मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का मानक तय किया जाता है, उन सब पर नजर रखी जा सकती है। हीटिंग थर्मोस्टेट, कैमरा, फिटनेस आर्म्बैंड जैसे घरेलू इंटीलेजेंट गैजेट भी इंटरनेट के जरिए पर्सनल डाटा भेजते हैं। डाटा सुरक्षा कार्यकर्ताओं की मांग है कि कंपनियों को डाटा ट्रांसफर सिस्टम को पारदर्शी बनाना चाहिए और यूजर से उनके डाटा के इस्तेमाल की अनुमति लेनी चाहिए। डाटा सुरक्षा भरोसे का महत्वपूर्ण कारक है। यदि आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपको ग्राहकों में भरोसा जमाना होगा। डाटा सुरक्षा के बिना यह पैदा नहीं होगा अगर भरोसे के बिना कारोबार नहीं चलेगा।



भूत है या नहीं यह सदियों से बहस का मुद्दा है। कोई कुछ भी कहे, हमारे समाज में इन पर विश्वास और अविश्वास की कई कहानियां हैं। रहस्य और रोमांच के इस खेल को समझने के लिए, उन पर रिसर्च के लिए कई पैरानॉर्मल संस्थाएं काम भी काम कर रही हैं। खास बात यह है कि पुराने जमाने की तरह यह इंस्टीट्यूट किसी ओझा या तांत्रिक के भरोसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि इनकी खोज का आधार हैं अत्याधुनिक गैजेट्स।

भारत में करीब 10 मान्यता प्राप्त पैरानॉर्मल सोसायटीज हैं, जो भूतों से बात करने और उनके रहस्य सुलझाने का दावा करती हैं। कुछ खास वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से इनके सदस्य भूतिया स्थानों की आदत और नमी का पता लगाकर, वहां हो रही पारलौकिक गतिविधियों को कैमरे और ऑडियो में कैद कर लेते हैं।

ऐसे ही गैजेट्स और उपकरणों की मदद से ‘टीम पेन्टेकल’ ने हाल ही में गोवा के जंगलों में कुछ भूतिया आवाजों को सुना और उन पैरालौकिक ताकतों को रिकॉर्ड भी किया है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही गैजेट्स के बारे में, जो पैरानॉर्मल सोसायटीज के सदस्यों द्वारा भूत-प्रेत और आत्माओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

सक्सैस के लिए परफेक्शन-पैशन जरूरी

तेजी से बदलते जमाने और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपनी जगह व पहचान बनाने के लिए अपनी पसंद के क्षेत्र में पैशन होना बेहद जरूरी है, तभी आप परफेक्शन के साथ अपने टास्क पूरे करते हुए कामयाबी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जानिए अपनी रुचि के क्षेत्र में पैशन होना क्यों है जरूरी है...

विविध

टीवी भी आपको देख रहा है...

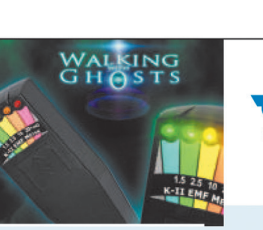


तो क्या स्मार्ट टीवी नहीं खरीदें?
जो नहीं, स्मार्ट टीवी जरूर खरीदें और यदि नहीं भी खरीदना चाहें तो क्रोमकास्ट जैसे डगल से अपने टीवी को स्मार्ट अवश्य बनाएं। आखिर दुनिया स्मार्ट हो रही है तो आपका टीवी क्यों

नहीं? हां, कुछ उपायों से आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं और अपने स्मार्ट टीवी का भरपूर उपयोग स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। स्मार्ट टीवी में दो प्रमुख बातें हो सकती हैं। आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए और आवाज और हावभाव से टीवी कंट्रोल करने व स्क्राइप जैसी सेवाओं से वीडियो टेलीफोनी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इसमें अंतर्निर्मित कैमरा तथा आवाज पहचानने हेतु रिमोट में माइक्रोफोन होता है। जब आप स्क्राइप जैसी सेवा चालू करते हैं तो यह स्वचालित सक्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप टीवी को आवाज या हावभाव से नियंत्रित करने हेतु तैयार कर देते हैं तो इसका कैमरा तथा आवाज पहचानने वाला माइक्रोफोन चालू हो जाता है और आपके हावभाव तथा आवाज को पहचान कर टीवी के फंक्शनों को नियंत्रित करता है। कुछ स्मार्ट टीवी के माइक्रोफोन हमेशा सुनने वाले मोड में होते हैं और जैसे ही आप कुछ पूर्व निर्धारित शब्द कहते हैं तो यह आपकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगते हैं कि आप आखिर क्या कहना या करना चाह रहे हैं और यदि आप कहेंगे हाथ टीवी स्टार्ट तो आपका टीवी चालू हो जाएगा, और आप कहेंगे हाथ टीवी शट डाउन तो यह बंद हो जाएगा। आमतौर पर, सामान्य उपयोग हेतु ये सेवाएं सुरक्षित, समस्या रहित मानी जाती हैं।

तो फिर समस्या कहां है?

समस्या वहां आ सकती है, जब आपका स्मार्ट टीवी आपकी आवाज को ठीक से पहचानने के लिए आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर रीयल टाइम में अपने क्लाउड सर्वरों अथवा फिर्ही तृतीय पक्ष की सेवा पाने के लिए (जैसे कि स्पीच रिकग्नीशन अथवा स्पीच टू टेक्स्ट / टेक्स्ट ट्रांसलेटर सेवा आदि के लिए) उनके क्लाउड सर्वरों पर अपलोड करता है। आमतौर पर सभी स्मार्ट टीवी यह करते हैं। स्थानीय रूप से ऑप्लेलाइन में आमतौर पर यह कार्य नहीं होता क्योंकि आपका स्मार्ट टीवी और उसमें रखा डेटाबेस इतना सक्षम नहीं होता और इस कार्य के लिए प्रायः ऑनलाइन डेटा और वृहद सक्षम तंत्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आप अपने स्मार्ट टीवी में अपनी आवाज का उपयोग करते हुए कोई खोज कर रहे हैं लेकिन इस बीच आप कुछ आपसी वार्तालाप भी कर लेते हैं तो वह सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और आपके स्मार्ट टीवी से संबद्ध सर्वरों पर पहचानने के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि आप कतई नहीं चाहेंगे। ऊपर से, यूक्रे आपका स्मार्ट टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड व ऑनलाइन होता है तो उसमें भी हैकिंग से नियंत्रण प्राप्त कर उसके बेजा उपयोग के खतरे वैसे भी हैं।



घोस्ट बॉक्स
घोस्ट बॉक्स या फ्रैंक बॉक्स एक तरह का पोर्टेबल रेडियो है, जिसमें एफ और एमएम बैंड भी कनेक्ट होता है। माना जाता है कि कई रहस्यमयी ताकतें ऑडियो संकेतों की मदद से अपना संदेश देती हैं। इस डिवाइस को डिजिटल रिकॉर्डर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

समस्या से कैसे निपटें?

अपने स्मार्ट टीवी को चलाने समय थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं। यदि अपने स्मार्ट टीवी का उपयोग ऑनलाइन नहीं कर रहे हों तो भले ही थोड़ा झंझट भरा हो, इसका नेट कनेक्शन बंद कर रखें। स्मार्ट टीवी का कैमरा यदि उपयोग में न आ रहा हो तो उसे बंद कर रखें। स्मार्ट टीवी की सेटिंग में मोशन रिकग्नीशन बंद कर रखें। टीवी पर माइक्रोफोन का चिह्न दिखाई दे रहा हो तो यह मान लें कि आपका स्मार्ट टीवी आसपास हो रही तमाम आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे में सावधानी बरतें तथा कार्य समाप्त हो जाने के बाद माइक्रोफोन बंद कर दें। आवाज नियंत्रण सुविधा का इस्तेमाल न करें या करें तो ध्यान रखें कि उस वक्त दूसरे किस्म के वार्तालाप न करें।



अब एक नई रणनीति

आप सोचिए कि आपके बॉस को यह डाटा मिल जाए। नौकरी के लिए आवेदन देने वालों को इस तरह की पर्सनेलिटी प्रोफाइल के आधार पर नौकरी मिल सकती है, या उनके आवेदन को ठुकराया जा सकता है या फिर कंपनियां इसके आधार पर लोगों का भविष्य तय करेंगी। आईटी को सुरक्षित बनाने पर काम कर रहे वैज्ञानिक इसके खिलाफ एक नई रणनीति बना रहे हैं। इसके केंद्र में यह बात है कि हर कोई खुद तय करेगा कि वह अपना डाटा देना चाहता है या नहीं। रिसर्चरों ने एक डाटा सेप्टी बॉक्स डेवलप किया है, जो यूजर को अपने डाटा का मालिक बनाता है। स्मार्ट टीवी के पीछे लगा छोटा सा कंप्यूटर बॉक्स, टीवी में आने जाने वाले डाटा पर नजर रखता है और जैसे ही कोई क्रिटिकल डाटा फ्लो दिखता है, तो मॉनिटर पर अलार्म भेज देता है। जैसे ही आप डाटा सेप्टी बॉक्स का संदेश देखते हैं, अपने रिमोट कंट्रोल पर ग्रीन बटन दबाकर फेसला कर सकते हैं कि चैनल को आपका डाटा मिलना चाहिए या नहीं। अगर आप बटन नहीं दबाते हैं, तो चैनल को आपका डाटा नहीं मिलेगा।

अब एक नई रणनीति

घोस्ट हंटिंग गैजेट्स...

डिजिटल रिकॉर्डर
डिजिटल रिकॉर्डर का छोटा नाम ईवीपी है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इसे ऐसी जगहों पर रहस्यमयी आवाजें सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस डिजिटल रिकॉर्डर की आवाज से आत्माओं को फॉलो किया जा सकता है।

मिस्टर घोस्ट

मिस्टर घोस्ट एक ईएमएफ डिटेक्टर है। इसे स्मार्टफोन के हेडफोन जैक से कनेक्ट घर में पारलौकिक गतिविधि का पता लगाया जा सकता है। दरअसल, यह एक ऐसी डिवाइस है, जो एम्प की मदद से रेडिएशन मापती है। इसे यूज करने के लिए स्मार्टफोन पर ‘मिस्टर घोस्ट’ नाम का एप्प डाउनलोड करना होता है। ईएमएफ डिटेक्टर को फोन से कनेक्ट करके उस दिशा में इंगित करना होता है, जहां से भूतिया गतिविधि होने की शंका हो। एंप की मदद से यह डिवाइस उस जगह से आ रही रेडिएशन बता देगी।

अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे पैशन बनाकर आगे बढ़ने वाले कभी भी भटकाव या दुविधा के शिकार नहीं होते। दरअसल, अपनी रुचि के क्षेत्र में पूरी तरह डूबकर ही वे अपनी मंजिल को आसान बना पाते हैं। जो दूसरों को देखकर उनकी राह का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, वे अपने भीतर छिपे गुणों को देख नहीं पाते। यही कारण है कि वे अपने मन की राह पर चलने की बजाय भटकाव के चौराहे पर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंच कर उन्हें यह सूझता ही नहीं कि अब किस राह पर वे आगे बढ़ें।

दूसरों की तरफ देखने की बजाय सबसे पहले तो आप यह देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी रुचियां किस तरह की हैं, किस तरह के काम करने में आपको मजा आता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता? इस प्रक्रिया में आपको अपनी रुचि का क्षेत्र जानने-समझने में

आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा फेसबुक...

आम लोगों के बारे में फेसबुक जितनी जानकारी इकट्ठु करता है कोई सोशल नेटवर्क नहीं करता। फेसबुक 98 तरह की जानकारी इकट्ठु करके उसी के हिसाब से ऑनलाइन विज्ञापन दिखाता है। फेसबुक आपकी लोकेशन, आपकी आय, आपकी पसंद-नापसंद, आपकी मौजूदा जरूरत, आपके पिछले सर्च, आपके निकटतम मित्रों से हुई आपकी बातचीत के कीवर्ड्स सब जानता है। इन सबसे मिलकर आपकी प्रोफाइल बनती है और उसके बाद विज्ञापन देने वाली कंपनी तय करती है कि उसे किस तरह की प्रोफाइल वाले लोगों तक पहुंचना है। जब भी आप फेसबुक पर लॉग इन होते हैं, ज्यादातर लोग तो कभी लाग आउट करते ही नहीं, तो फेसबुक को यह पता चलता रहता है कि इस वक़्त आपकी ऑनलाइन गतिविधियां क्या हैं, आप किस साइट पर हैं वगैरह। यहां तक कि लॉग ऑफ करने के बाद भी फेसबुक के पास आपके बारे में काफी जानकारी पहुंचती रहती है। हर बार जब आप कोई पेज लाइक या शेयर करते हैं तो उसके बारे में फेसबुक के पास पूरी जानकारी तो होती ही है। अब बहुत-सारी ऑनलाइन कंपनियां आपको फेसबुक लॉग इन का इस्तेमाल करने के लिए कहती हैं, यानी उस साइट या ऐप पर आप जो भी करेंगे वो फेसबुक को मालूम होगा।

facebook

आपका पूरा हिसाब

फेसबुक इस बात का पूरा हिसाब रखता है कि आपकी पसंद-नापसंद, जीवनशैली, आदतें और जरूरतें क्या हैं, उसी हिसाब से वह टारगेट विज्ञापन करके मोटी कमाई करता है। हर बार जब आप लॉग इन करके थोड़ा समय फेसबुक पर बिताते हैं तो उसकी कमाई कुछ बढ़ जाती है। फेसबुक के सभी सब्सक्राइबर अपने बारे में जानकारी खुद ही देते रहते हैं। लोग उसकी वेबसाइट को भी एक्सेस करके उस पर तरह-तरह की जानकारी जैसे ईमेल, मोबाइल फोन नंबर, शहर के अलावा कई और भी जानकारी देते हैं। यह ऐसी जानकारी होती है जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह, बच्चों के नाम – जो ग्राहकों के बारे में मिलना आसान नहीं है और जब लाखों लोगों के बारे में यह जानकारी मिल सकती है तो उसके लिए एक कौमत् चुकाने में कंपनियां नहीं हिचकती हैं। लोकेशन के बारे में जानकारी देकर लोग फेसबुक को यह भी बताते हैं कि वो साल में कितनी बार छुट्टियां मनाने जाते हैं, कितनी बार घर से बाहर खाना खाते हैं या पिकर देखने जाते हैं। बियर के गिलास के साथ आप अपनी तस्वीर शेयर करेंगे तो आपको पबों और बारों के विज्ञापन दिखाई देने लगेंगे जो शराब नहीं पीता उसको ऐसे ऐड दिखाकर क्या फायदा? अगर आपने अपनी नई कार की तस्वीर शेयर की है और आपकी लोकेशन भी मालूम है, मिसाल के तौर पर आपके शहर में महंगी कार चलाने वाले लोगों के समूह को ही महंते सामान का विज्ञापन दिखाया जाए, ऐसे फिलेले करना काफी आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोलकट बनाने वाली कंपनियां तय कर सकती हैं कि सिर्फ टीनएजर लड़कियों को ही अपने विज्ञापन दिखाने हैं लेकिन अगर कोई फिटनेस ट्रैकर जैसे प्रोडक्ट बेच रहा है तो 30 साल के ऊपर लोगों तक भी पहुंचना चाहेगा। ऐसे लोग जब अपने फेसबुक पेज पर लॉग इन करेंगे तो उन्हें वो विज्ञापन ही दिखाई देंगे। ये सभी कंपनियां फेसबुक को इसके लिए भरपूर पैसे देती हैं क्योंकि टीवी या प्रिंट के विज्ञापन इतने निशाने पर नहीं लगते। सब्सक्राइबर को उनके जन्मदिन पर फेसबुक पेज पर कंपनियों की तरफ से बधाई संदेश भी भेजा जा सकता है क्योंकि ये जानकारी लोग खुद ही फेसबुक को देते हैं। गूगल पर अगर आप खरीदने के लिए घंडियां ढूंढ़ रहे हैं तो फेसबुक पर भी उसके विज्ञापन दिखाई देने लगते हैं, ऐसा संयोगवश ही, बल्कि रणनीति के तहत होता है।

आपसे क्या चाहता है फेसबुक

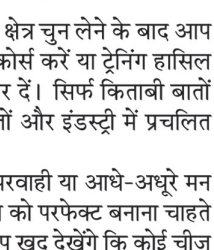
ऐसा नहीं है कि फेसबुक के बारे में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जो औसत समय लोग फेसबुक पर बिताते हैं वो कम हो रहा है, जो विज्ञापन देने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो वो फेसबुक के लिए चिंता की बात हो सकती है इसीलिए फेसबुक चाहता है कि आप उसकी वेबसाइट से लॉग आउट न करें ताकि आपका स्टेटस हमेशा लॉग इन चला रहे। ऐसे में कंपनियों को लगेगा कि आप ज्यादा समय फेसबुक पर बिता रहे हैं। स्मार्टफोन पर विज्ञापनों से कमाई में फेसबुक, ट्विटर के मुकाबले काफी आगे निकल गया है और अब गूगल के अलावा दूसरी कोई भी कंपनी उसे टक्कर देने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है।

लेजर गिड

यह एक तरह की लेजर डिवाइस है, जिसमें आसपास आत्मा या शक्ति होने पर लेजर बीम जलने लगती है। घोस्ट इन्वेस्टिगेशन में इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कैमरा और कैम-कॉर्डर भी लगाया जाता है। बाजार में तरह-तरह के फीचर्स वाले कई लेजर गिड उपलब्ध हैं।

इन्फ्रारेड थर्मामीटर

इन्फ्रारेड थर्मामीटर को थर्मल स्कैनर के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई शक्ति नजदीक होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और तापमान में भी जरा-सा अंतर आ जाता है। इन दोनों चीजों को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता हैं। माना जाता है कि ऐसी शक्तियां जहां होती है वहां टंड ज्यादा रहती है। अगर तापमान 10 डिग्री के नीचे चला जाए, तो यह किसी शक्ति के होने का अहसास बताता है। घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स सभी भूतिया जगहों पर इसे जरूर लेकर जाते हैं। अन्य कई उपकरणों के साथ इसकी रीडिंग को भी काफी प्रमुखता दी जाती है।



सहायता मिल सकती है। एक बार अपने मन का क्षेत्र चुन लेने के बाद आप उस पर कदम आगे बढ़ाएं। इसके लिए जरूरी कोर्स करें या ट्रेनिंग हासिल करें। थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल पर भी जोर दें। सिर्फ किताबी बातों की बजाय आज के समय की व्यावहारिक बातों और इंडस्ट्री में प्रचलित तकनीकों को जानें-समझें।

जो कुछ भी सीखें, उसमें पूरी तरह डूबें। लापरवाही या आधे-अधूरे मन से आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। अगर अपने को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो सीखने में जी-जान लगा दें। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि कोई चीज सीख लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। इस तरह से आगे बढ़ने पर आपको काम नहीं ढूंढ़ना पड़ेगा, बल्कि इसके उलट काम आपके पीछे-पीछे चलेगा। हुनर के पारखी लोग आपको बुलाकर नौकरी देंगे।

जब तक अमित शाह जवाब नहीं देते, विरोध जारी रहेगा: खेड़ा

नईदिल्ली। 20 जुलाई के संसद चलोमार्च के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने अपना विरोध तेज़ कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्रवाई पर सवालों का जवाब नहीं देते, तब तक संसद में यह मुद्दा उठाया जाता रहेगा। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया कि सिर्फ़ आंदोलन होने से पुलिस की ज्यादाती को सही नहीं ठहराया जा सकता। पत्रकारों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री जवाब नहीं देते, हम अपनी मांग (20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के लिए जवाबदेही) उठाते रहेंगे... हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यह बात कही। महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ; सादे कपड़ों में वे लोग कौन थे? क्या वे आरएसएस के गुंडे थे? यह सब दिल्ली पुलिस के सामने हुआ।

छात्रों पर नहीं, हमलावरों पर करें कार्रवाई: राहुल गांधी

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ एके-47 राइफल के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मांग की कि छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगें राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, छात्रों के खिलाफ पूरी की पूरी व्यवस्था जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एके-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने लिखा, मोदी जी, कहां गया आपका वह वादा कि छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टे उनके खिलाफ घातक हमले और बर्बरता की जा रही है।

प्रदर्शन के लिए देशव्यापी प्रोटोकाल बनाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर छिड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद स्पष्ट और अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है और केवल यह कहकर कि कहीं आंदोलन चल रहा था, पुलिस की कथित ज्यादातियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने साफ संकेत दिए कि अब पूरे देश में विरोध-प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है, ताकि लोकतांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहें और कानून-व्यवस्था भी कायम रहे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी 20 जुलाई को कथित नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन और पिछले सप्ताह दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।

13 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रोके ईरान पर हमले

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पिछले 13 दिनों से लगातार जारी सैन्य हमलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है. करीब दो सप्ताह से रोजाना हो रहे हमलों के बीच यह पहला मौका है जब अमेरिका ने नए सैन्य अभियान को रोकने का फैसला किया है.रिपोर्ट्स के अनुसार, नए हमले की योजना तैयार होने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना को फिलहाल कोई नई स्ट्राइक नहीं करने का निर्देश दिया है. व्हाइट हाउस का ध्यान अब सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है. हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि परिस्थितियां बदलती हैं या जरूरत पड़ती है, तो सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की पूरी तैयारी रखी गई है. इनमें ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को अवसर देना, अमेरिका के मिसाइल रक्षा भंडार में कमी को लेकर बढ़ती चिंता और संघर्ष के व्यापक युद्ध में बदलने की आशंका प्रमुख मानी जा रही है.

पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम!

पंजाब। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से होने वाली एक बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ किया है. पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आपसआई समर्थित और बम्बर खालसा इंटरनेशनलसे जुड़े एक बड़े आतंकी मांड्यूल का पर्दाफाश करने में सफलता पाई है. जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस और जालंधर देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है. पंजाब छवक्कने झ्र पर जानकारी देते हुए बताया है कि जालंधर देहात पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है. पुलिस का कहना है कि यह मांड्यूल विदेश में बैठे उनके आकाओं के इशारे पर काम करता था. आरोपी के पास से 1.3 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव से भरा आईईडी बरामद किया गया है. फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है. आईईडी में लोहे की छर्ने और ताँक भारी नुकसान हो. जाहेर है ये आतंकी पंजाब में किसी बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने वाले थे. इस कार्रवाई से राज्य में शांति-व्यवस्था भंग करने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है।

गृह मंत्री के जवाब की मांग को लेकर लोकसभा में हंगामा

नईदिल्ली। नीट प्रश्नपत्र लोक मामले में गत सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग करते हुए सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई और आज भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सदन की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष बिरला ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय वेट लिफ्टर मीराभाई चानू समेत अन्य पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी।

इसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के आगे आ गए। वे दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे। बिरला ने कहा कि वह पहले ही यह व्यवस्था दे चुके हैं कि प्रश्नकाल में केवल सदस्य सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और अन्य कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा।

उन्होंने शोर-शराबा कर रहे विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर जाकर बैठने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, “भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस सदन की मर्यादाओं और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की है।” उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों को



कार्रवाई की चेतावनी देते हुए यह भी कहा, “मैं कुछ दिन से सदस्यों का व्यवहार देख रहा हूं। यह व्यवहार सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

मुझे ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।” बिरला ने कहा, “आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो लेकिन तख्तियां लेकर यहां आना उचित नहीं है।” शोर-शराब नहीं थमा तो अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन में आज भी प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और नीट प्रश्नपत्र लोक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पिछले पूरे सप्ताह प्रश्नकाल नहीं चल सका था।

पेपर लीक रोकने वाले विधेयक पर रिजिजू ने विपक्ष से की वर्चा की अपील

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर विपक्ष से सदन में चर्चा की अपील की। उन्होंने कहा कि देशभर के छात्रों की चिंताओं को देखते हुए यह महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी सदस्य इस

पर चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहे हैं।

किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा

सुधारों को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी और समयबद्ध सजा का प्रावधान किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस और विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन में खुली और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इतने बड़े सुधारों के बाद भी चर्चा नहीं होने दी जाती है, तो इससे गलत संदेश जाएगा। रिजिजू ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा और बहस के लिए संसद से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि हंगामा करने के बजाय छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा सुधार विधेयक पर गंभीर चर्चा की जाए।

पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन

नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने सोमवार को संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी

वाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की।

कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां और बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की है। सांसदों ने गृह मंत्री से इस मामले में जवाब देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संकेत दिए हैं कि वे संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लगातार उठावेंगे। विपक्ष का कहना है कि छात्रों पर हुई कथित हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित बर्बर हमले की निंदा करते हुए पूछा है कि क्या प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन जैसे घातक बल के इस्तेमाल की मंजूरी गृह मंत्री ने दी थी।

राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाले। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हुई कथित हिंसा ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाई है और इससे पूरे देश में आक्रोश है। युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उनकी मांगों का जवाब सरकार को देना होगा।

भाजपा ने राहुल पर एके 47 संबंधी झूठा दावा कर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एके-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने मांग की है कि राहुल गांधी “झूठी बातें और गलत जानकारी” फैलाने के लिए माफी मांगें।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजित पात्रा ने गांधी के बयान को “न केवल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बल्कि एक पाप” करार दिया। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि खबरों से पता चलता है कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एके-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने छात्रों पर कथित हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

लोकसभा सदस्य संजित पात्रा ने कहा कि यह “बहुत शर्म की बात” है कि विपक्ष के नेता ने “इतना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार” दिखाया है। पात्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, “उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा एके-47 के इस्तेमाल की बात कही, लेकिन यह अत्यंत निंदनीय है कि भारत में विपक्ष के नेता के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी गलत बातें फैलाई जा रही हैं।” गांधी से माफी की मांग करते हुए पात्रा ने कहा, “वह झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एके-47 – मैं राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए इस शब्द पर जोर दे रहा हूं।

क्या इस देश में पुलिस कभी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए एके-47 का इस्तेमाल करती है? क्या ऐसा कभी हुआ है?” उन्होंने कहा, “राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि एके-47 का इस्तेमाल किया गया है? यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और हमारा दृढ़ विश्वास है कि राहुल गांधी को ऐसी झूठी बातें और गलत जानकारी फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।” केंद्रीय मंत्रियों जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत के बाद काँकरोच



जनता पार्टी (काँजपा) द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन वापस लिए जाने का जिक्र करते हुए, पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी अब देश में घबराहट और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “आप सभी ने देखा कि कैसे काँजपा ने खुद विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद घोषणा की गई कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है।” पात्रा ने कहा, “इस तरह का प्रचार करके और गलत जानकारी फैलाकर, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घबराहट, अव्यवस्था और अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है।” पात्रा ने लोगों से अपील की कि वे गांधी के बयान को गंभीरता से न लें और इसके बजाय “सच सामने लाएं ताकि देश में अराजकता न फैले।”

उन्होंने कहा, “मैं राहुल गांधी से यह भी कहूंगा कि उन्हें जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार करना चाहिए और ऐसे गुमराह करने वाले दावे फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।” पात्रा ने आरोप लगाया, “स्वाभाविक रूप से, राहुल गांधी का मकसद (मुद्दों को) सुलझाना नहीं है। हंगामा खड़ा करने की कोशिश करना, बनावटी गुस्सा पैदा करने की कोशिश करना, विरोध प्रदर्शन खड़ा करने की कोशिश करना और सबसे बढ़कर अराजकता फैलाने की कोशिश करना ही राहुल गांधी और विपक्ष के नेता का एकमात्र मकसद है।

स्टोल प्रमुख समाचार

जूनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आगाज आज

नईदिल्ली। भारतीय हॉकी के भविष्य को नई दिशा देने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आगाज 28 जुलाई से तमिलनाडु के कोयंबटूर में होगा। देशभर की 30 टीमों अगले 12 दिनों तक राष्ट्रीय खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 8 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें डिवीजन-ए का विजेता राष्ट्रीय चैंपियन बनेगा।

इस बार टूर्नामेंट को डिवीजन-ए, डिवीजन-बी और डिवीजन-सी में बांटा गया है। डिवीजन-ए की टीमें राष्ट्रीय खिताब के लिए खेलेंगी, जबकि डिवीजन-बी और डिवीजन-सी की टीमों अगले स्तर पर प्रमोशन हासिल करने की कोशिश करेंगी। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली टीमों को रेलिगेशन का सामना करना पड़ेगा।

डिवीजन-ए में कुल 12 टीमों चार पूलों में बांटी गई हैं। पूल-ए : हॉकी हरियाणा, हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी यूनित ऑफ तमिलनाडु। पूल-बी: हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, मणिपुर हॉकी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव हॉकी। पूल-सी: हॉकी पंजाब, हॉकी झारखंड, दिल्ली हॉकी। पूल-डी: उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी कर्नाटक, हॉकी बंगाल।

प्रत्येक पूल से शीर्ष दो टीमों 5 अगस्त को होने वाले क्वाटरफाइनल में पहुंचेंगी। इसके बाद 6 अगस्त को सेमीफाइनल और 8 अगस्त को कांस्य पदक मुकाबला तथा फाइनल खेला जाएगा। डिवीजन-ए की सबसे निचली दो टीमों अगले सीजन में डिवीजन-बी में चली जाएंगी।

पहले दिन इन मुकाबलों पर रहेगी नजर

28 जुलाई को प्रतियोगिता की शुरुआत डिवीजन-सी के मुकाबलों से होगी। असम हॉकी बनाम हॉकी मिजोरम- सुबह 6:00 बजे। गोअन्स हॉकी बनाम हॉकी राजस्थान- सुबह 7:30 बजे। तेलंगाना हॉकी बनाम त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन - सुबह 9:00 बजे। ले पुडुचेरी हॉकी बनाम हॉकी गुजरात - सुबह 10:30 बजे। इसके बाद डिवीजन-बी के मुकाबले खेले जाएंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार



शैलेश डोभाल

भारत के शीर्ष 100 शहरों में आमदनी, ख़ात और बचत के मामले में सबसे संपन्न 3.5 से 5 करोड़ उपभोक्ताओं पर अब तक कंपनी और मार्केटिंग जगत का सबसे अधिक ध्यान रहा है। आर्थिक मंदी या दिक़तों के बीच भी ख़रीदने की उनकी क्षमता बनी रहती है, जिसका उदाहरण कोविड-19 महामारी के बाद अंग्रेज़ी के ‘के’ अक्षर की तरह दिखने वाला असमान सुधार है, जिसमें कुछ क्षेत्र डूबते रहे और कुछ तेज़ी से उठ गए।

लेकिन अब स्थिति बदल रही है। रोज़मर्रा की वस्तुओं से लेकर महंगे सामान तक, पूरे बाज़ार में मांग सुस्त पड़ती दिख रही है, जिस कारण निजी क्षेत्र भी क्षमता विस्तार में नया निवेश करने से हिचक रहा। साबुन, शैंपू, दोपहिया वाहन, वॉशिंग मशीन, कपड़े और कार तक बेचने वाली छोटी-बड़ी सभी कंपनियां अब उन 20 करोड़ शहरी

उपभोक्ताओं पर ध्यान दे रहे हैं, जो मोटी आय वाले उन 3.5 से 5 करोड़ लोगों वाले तबके के ठीक नीचे हैं।

शोध संस्था पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकॉनमी (प्राइस) और टाटा संस की संयुक्त रिपोर्ट ‘द मैनी अर्बन इंडियाज’ इस बड़े उपभोक्ता बाज़ार की स्पष्ट तस्वीर सामने रखती है। अधिकतर मीडिया रिपोर्ट इस अध्ययन में दिए गए चार शहरी वर्गों की बात करती हैं, जिनमें भारत के शीर्ष 100 शहरों को आबादी के हिसाब से बांटा गया है। ये वर्ग हैं, बिग सिक्स (1 करोड़ से अधिक आबादी वाले छह महानगर), बूमटाउन्स (25 लाख से 1 करोड़ आबादी वाले 19 शहर), ब्रेकआउट सिटीज (15 से 25 लाख आबादी वाले 25 शहर) और फ्रंटियर सिटीज (5 से 15 लाख आबादी वाले बाकी 50 शहर)।

किंतु इस अध्ययन में एक पहलू को ज्यादातर ने नज़रअंदाज किया है और वह है



आय के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण तथा शीर्ष 100 शहरों में मध्यम आय वर्ग के बढते महत्त्व पर विशेष जोर। इन 100 शहरों में भारत की 19 प्रतिशत आबादी बसती है मगर 35 प्रतिशत आय यहीं आती है, 31 प्रतिशत खर्च यहीं से होता है, परिवारों की 47 प्रतिशत अतिरिक्त आय इन्हीं शहरों में होती है और करीब दो-तिहाई शहरी मांग भी यहीं से आती है।

भारत के शीर्ष 100 शहरों में 6.2 करोड़ परिवार रहते हैं और अध्ययन के अनुसार 2025–26 तक उनमें से आधे से ज्यादा (53

प्रतिशत) मध्यम आय वर्ग का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2025–26 की कीमतों के आधार पर 6 लाख से 36 लाख रुपये के बीच मानी गई है। दस वर्ष पहले इनमें से आधे परिवार ही इस आय वर्ग में थे और अनुमान है कि 2030–31 तक इन शहरों में 8 करोड़ परिवार हो जाएंगे, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक मध्यम आय वर्ग के होंगे। अध्ययन के अनुसार भारत में इस वर्ग की प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) लगभग 15 से 90 डॉलर रोजाना है, जो मध्यम आय वर्ग की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा से मेल खाता है। उदाहरण के लिए ब्रूक़िंस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से पीपीपी 11 से 110 डॉलर रोजाना और प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 10 से 20 डॉलर रोजाना है। हर परिवार में औसतन 4.6 सदस्य मानें तो इस वर्ग में लगभग 20 करोड़ उपभोक्ता बैठते हैं। अध्ययन के अनुसार आय

के आधार पर परिवारों की अन्य श्रेणियां निम्न आय वर्ग (सालाना 1.5 लाख रुपये से कम आय), निम्न-मध्यम आय वर्ग (सालाना 1.5 लाख से 6 लाख रुपये के बीच) और उच्च आय वर्ग (वार्षिक आय 36 लाख रुपये से अधिक) हैं। आने वाले वर्षों में मध्यम आय वर्ग सभी प्रकार के शहरों में बराबर फैलेगा और 2031 तक बिग सिक्स में 63 प्रतिशत परिवार, बूमटाउन्स में 59 प्रतिशत, ब्रेकआउट सिटीज में 57 प्रतिशत और फ्रंटियर सिटीज में 56 प्रतिशत परिवार इसी वर्ग से होंगे। प्राइस–टाटा संस की रिपोर्ट इसे भारत के शहरी इतिहास में सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता का सबसे बड़ा बदलाव बताते हुए कहती है कि इस दौरान भारत में उच्च आय वर्ग की हिस्सेदारी बढ़कर 19.6 प्रतिशत हो जाएगी और निम्न वर्ग की घटकर केवल 0.4 प्रतिशत तथा निम्न-मध्यम आय वर्ग की लगभग 20 प्रतिशत रह जाएगी।

जल जीवन मिशन 2.0 पर सांसदों के साथ मंथन

छत्तीसगढ़ सदन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन

रायपुर। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सोमवार शाम जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव सहित राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद उपस्थित रहे। बैठक में सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की प्रगति, योजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ के लोकसभा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, श्री चिंतामणि महाराज, श्री राधेश्याम राठिया, श्रीमती



कमलेश जांगड़े, श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्री संतोष पांडेय, श्री विजय बघेल, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, श्री महेश कश्यप और श्री भोजराज नाग तथा राज्यसभा सांसद राजा देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और श्रीमती फूलो देवी नेताम उपस्थित रहे।

बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, परियोजनाओं में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया।

सांसदों ने अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े सुझाव और आवश्यकताएं भी साझा की। बैठक में मिशन के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से योजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।

अधिकारियों ने जल जीवन मिशन 2.0 की प्रमुख विशेषताओं और क्रियान्वयन रणनीति की भी जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में सांसदों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे जिला स्तरीय छद्म की

बैठकों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं के समाधान में सहयोग करें। साथ ही, रजल अर्पणश कार्यक्रमों में सहभागिता कर पूर्ण हो चुकी पेयजल योजनाओं के लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतों को उनके हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें। जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने का भी आह्वान किया गया। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारियों सहित छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक भी उपस्थित रहे।

महापौर ने भाठागांव में दुकानों का आबंटन शीघ्र करने के लिए निर्देश



रायपुर। आज रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम जोन 6 क्षेत्र अंतर्गत भाठागांव में निर्मित बाजार परिसर का प्रत्यक्ष निरीक्षण नगर निगम जोन 6 जोन अध्यक्ष बद्धी प्रसाद गुप्ता, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड पार्षद रवि सोनकर, नगर निगम उपायुक्त बाजार डॉ अजलि शर्मा एवं अन्य संबंधित नगर निगम बाजार विभाग कर्मचारियों की उपस्थिति में किया एवं भाठागांव बाजार में दुकानों का आबंटन पूर्ण पारदर्शिता के साथ व्यवस्थित रूप से नियमानुसार शीघ्र करवाना प्रार्थमिकता से सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया है।

महापौर मीनल चौबे ने भाठागांव बाजार में दुकानों के आबंटन के पूर्व बाजार परिसर में स्वच्छता कायम कर चबूतरो की

■ **क्रिस्टल आर्केड के सामने वर्षों पूर्व ऑक्सीजीन विकास के कारण खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 69 दुकानदारों का सहमति अनुसार व्यवस्थापन शीघ्र करवाने की तैयारी के दिव्ये निर्देश**

नियमानुसार नंबरिंग बाजार में आवश्यकता अनुसार बेरिकेटिंग किया जाना, समुचित प्रकाश, पेयजल, सफाई की व्यवस्था करवाकर नागरिकों एवं व्यवसायियों के लिए शीघ्र अच्छी व्यवस्था कायम करने भाठागांव बाजार को पूरी तरह तैयार करने के निर्देश दिये है।महापौर मीनल चौबे ने क्रिस्टल आर्केड के सामने वर्षों पूर्व खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 69 दुकानदारों का मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कायम सहमति के अनुसार शीघ्र व्यवस्थापन करने की तैयारी करने के निर्देश नगर निगम बाजार विभाग के अधिकारियों को दिये है। महापौर ने सहमति के अनुसार उक्त कार्यवाही व्यवस्थित रूप से प्रक्रिया के तहत करवाने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया।

कारगिल के वीरों का बलिदान भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज रहेगा : उच्च शिक्षा मंत्री

रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सभागृह में आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री ने कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, युवाओं की भूमिका और 2047 के विकसित भारत संकल्प पत्र पर अपने विचार साझा किए। मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को %ऑपरेशन विजय% के तहत भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए शत्रुओं को खदेड़ा था।कारगिल की जीत केवल सैन्य अभियान की सफलता नहीं, बल्कि भारत के अखंड स्वाभिमान की विजय थी। हमारे वीर जवानों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और



उनके परिवारों के प्रति पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से आभार जाताय। उच्च शिक्षा मंत्री ने देशभक्ति की परिभाषा को व्यापक रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति केवल विशेष अवसरों पर नारे लगाने तक सीमित नहीं है। समय का पाबंद होना, ईमानदारी से काम करना, ज़रूरतमंदों की मदद, जल व पर्यावरण संरक्षण, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान %एक पेड़ मौं के नाम% व %चोकल फॉर लोकल% को जीवन में अपनाना ही वास्तविक देशभक्ति है। र्गिजटल दौर की चुनौतियों का जिक्र करते हुए

उन्होंने कहा कि बिना जांचे-परखे फर्जी संदेश फैलाना सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही, हाल ही में नीट परीक्षा विवाद जैसे मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं का माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले असमाजिक और बाहरी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। उन्होंने राज्य के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के परिसरों में शांति, सुरक्षा और सुचारू अध्यापन के लिए सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत दी। मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के %विकसित भारत 2047% के विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के %समुद्ध छत्तीसगढ़% के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

प्रदेश में खाद-बीज की कमी नहीं

रायपुर। खरीफ 2026 के दौरान डीएपी की राष्ट्रीय स्तर पर सीमित उपलब्धता के बावजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश के प्रत्येक किसान को समय पर खाद-बीज उपलब्ध हो, किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और उर्वरकों की कालाबाजारी अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी के अनुरूप सरकार की कृषि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं मूल्य नियंत्रण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।खरीफ सीजन 2026 के लिए डीएपी का लक्ष्य 3 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। जबकि 21 जुलाई 2026 की स्थिति में प्रदेश में एक लाख 84 हजार 413 मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण किया गया है। वहीं भंडारण के विरुद्ध किसानों को एक लाख 26 हजार 360 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। इसके बाद भी समितियों एवं गोदामों में अभी 58 हजार 054 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2025 की इसी अवधि में 37 हजार 535 मीट्रिक टन डीएपी शेष था।प्रासन द्वारा कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुरूप किसानों को डीएपी के साथ-साथ एनपीके एवं अन्य संतुलित उर्वरकों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे फसलों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा डीएपी पर अत्यधिक निर्भरता कम हो। देश में डीएपी का लगभग 70 से 80 प्रतिशत तथा एनपीके का 30 से 40 प्रतिशत आयात विदेशों से किया जाता है।

स्मार्ट मीटर से बिजली खपत नहीं बढ़ती तीन शहरों के सर्वे में सामने आई सच्चाई

■ **रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के तुलनात्मक अध्ययन में जुलाई माह में बिजली खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज**



रायपुर। स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भांतियों और अफवाहों के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगे घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत का तीन माह का तुलनात्मक अध्ययन कराया है। मई, जून और जुलाई 2026 की खपत के विश्लेषण में यह सामने आया कि अधिकांश उपभोक्ताओं की बिजली खपत जुलाई माह में कम हुई है।

रायपुर शहर क्षेत्र के 3,11,374 घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अध्ययन में 1 जून से 26 जून 2026 के दौरान कुल बिजली खपत लगभग 10.85 करोड़ यूनिट दर्ज की गई थी,

जबकि 1 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान यह घटकर लगभग 7.77 करोड़ यूनिट रह गई। अर्थात कुल 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यदि 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की बात करें, तो 1 लाख 21 हजार 135 उपभोक्ताओं के बिलों के विश्लेषण से पता चलता है, कि उनकी खपत में लगभग 44 प्रतिशत की कमी हुई है। कारण स्पष्ट है, कि खपत का आधार स्मार्ट मीटर नहीं अपितु उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही वास्तविक खपत है। ऐसे उपभोक्ता जिनके आवासों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे उनकी खपत में भी माह अप्रैल-मई-जून में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई है।

उदाहरण:- अर्बती विहार रायपुर- उपभोक्ता क्र. 100060XXXX, संयोजित भार 5 किलोवाट, अप्रैल-

2025 की खपत 1611 यूनिट, अप्रैल- 2026 की खपत 2071 यूनिट , मई- 2025 की खपत 1503 यूनिट, मई- 2026 की खपत 2592 यूनिट, जून- 2025 की खपत 895 यूनिट, जून- 2026 की खपत 2487 यूनिट, राजीव नगर रायपुर- उपभोक्ता क्र. 100000XXXX, संयोजित भार 10 किलोवाट, अप्रैल- 2025 की खपत 1019 यूनिट, अप्रैल- 2026 की खपत 1065 यूनिट , मई- 2025 की खपत 885 यूनिट, मई- 2026 की खपत 1383 यूनिट, जून- 2025 की खपत 896 यूनिट, जून- 2026 की खपत 1762 यूनिट, कचना रायपुर- उपभोक्ता क्र. 100658XXXX, संयोजित भार 8 किलोवाट, अप्रैल- 2025 की खपत 1332 यूनिट, अप्रैल- 2026 की खपत 1360 यूनिट , मई- 2025 की खपत 1156 यूनिट, मई- 2026 की खपत 1709 यूनिट, जून- 2025 की खपत 759 यूनिट, जून- 2026 की खपत 1579 यूनिट।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

सहकारिता मंत्री 28 जुलाई को लेंगे विभागीय समीक्षा बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक की घोषणा की गई है। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में यह उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कल 28



जुलाई को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। यह बैठक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक), नवा रायपुर के सभा कक्ष में अ। य। र. फिज. त होगी।बैठक का मुख्य उद्देश्य सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना है। इस ?समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारियों, प्रबंध संचालकों, संभागीय संयुक्त आयुक्तों, उप/सहायक आयुक्तों एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जानकारी सहित उपस्थित रहने को कहा गया है। ? समीक्षा बैठक के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में चल रही योजनाओं को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन 28 जुलाई को किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के कोर्टयार्ड-बाइ-मेरियट होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और नामचीन खिलाड़ी राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं, प्रशिक्षण और अधोसंरचना के रोडमैप पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी शाम के सत्र में शामिल होंगे। वे इस दौरान इस साल छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम खेाईडिया ट्राइबल गेम्स में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव सबरे 11 बजे कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे।28 जुलाई को दिनभर चलने वाले स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के अलग-अलग 7 सत्रों में विशेषज्ञ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, क्षमता विकास, स्पोर्ट्स साइंस, उच्च स्तर पर भागीदारी, खेल के लिए बेहतर माहौल व सुविधाएं तैयार करने और खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने जैसे विविध विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। कॉन्क्लेव के समापन सत्र में सभी सत्रों में हुई चर्चा के निष्कर्ष साझा किए जाएंगे। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए इन निष्कर्षों को अमल में लाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में %लीडरशिप, खेल प्रोत्साहन एवं प्रतिभा पहचान% विषय पर अपने विचार रखेंगे।

छत्तीसगढ़ किकबॉक्सिंग संघ का चुनाव, छगन मूंदड़ा फिर बने प्रदेश अध्यक्ष



रायपुर। किकबॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ की वार्षिक साधारण सभा की बैठक एवं चुनाव सोमवार को हुआ। चुनाव अधिकारी अनिल मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक संचालक (खेल), लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि एसोसिएशन की नई प्रबंध कारिणी का चुनाव सत्र 2026 से 2030 के लिए संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा नामित पर्यवेक्षक प्रवेश जोशी, सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर की उपस्थिति में हुआ। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से छगन मूंदड़ा को पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया। भौगोलिकसंदर्भाकार्यकारी अध्यक्ष के पद पर तारकेश मिश्रा, महासचिव आकाश गुरुदीवान एवं कोषाध्यक्ष प्रभात साहू चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर मनीष बाग, रघुनाथ नायक, व्यंकेश दास मानिकपुरी, संकल्प तिवारी तथा संयुक्त सचिव के लिए प्रीति मिश्रा, रोशनी सेन, स्वाति राजवाड़े, अमन सोनी चुने गए।

पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज हेतु आरएफपी तैयार

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा मोवा (विधानसभा रोड) स्थित गारमेट फैक्ट्री के पुनर्जीवन, आधुनिकीकरण एवं संचालन हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर रिक्लेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार किया गया है। इस पहल के माध्यम से शीघ्र ही गारमेट फैक्ट्री के संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।परियोजना के अंतर्गत चयनित संस्था को 30 वर्ष की लीज़ पर फैक्ट्री परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित संस्था द्वारा अपने व्यय पर आवश्यक मशीनरी की स्थापना, आधुनिकीकरण, संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया जाएगा,



जिससे बंद पड़ी गारमेट फैक्ट्री का पुनः संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।इस परियोजना से विशेष रूप से महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा स्थानीय युवाओं को भी रोजगार एवं कौशल विकास का लाभ मिलेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में उद्योग विभाग का सहयोग प्राप्त होगा तथा राज्य शासन की औद्योगिक नीतियों के अनुरूप वस्त्र एवं रेडीमेड गारमेट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।इस पहल से नगर निगम की निष्क्रिय परिसंपत्ति का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा, स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा नगर निगम की आय में भी वृद्धि होने की संभावना है।

मीटर रीडरों ने सीएसईबी मुख्यालय का किया घेराव



रायपुर। प्रदेशभर में आज बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. एक ओर कांग्रेस का सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन जारी है. दूसरी ओर बिजली मीटर रीडरों ने भी राजधानी में मोर्चा खोल दिया है. विद्युत मीटर रीडर श्रमिक संघ के बैनर तले प्रदेशभर से मीटर रीडर सोमवार को सीएसईबी मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं. इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है. डडसेना भवन में मीटर रीडरों के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे. रअसल, प्रदेशभर में स्मार्ट बिजली व्यवस्था लागू होने से वर्षों से कार्यरत मीटर रीडरों के आगे आजीविका का संकट खड़ा हो गया है. कई जिलों में महीनों से मानदेय भुगतान लुप्त है. अलग-अलग दरों से भुगतान किए जाने के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष है. मीटर रीडरों का कहना है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से प्रभावित मीटर रीडरों के रोजगार को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

अर्पण दिव्यांग स्कूल में बच्चों को गणवेश एवं कापी किताब वितरण

रायपुर। अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में आज बच्चों को गणवेश एवं कापी किताब बच्चों को वितरित की गई। मुख्य अतिथि शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन तथा विशिष्ट अतिथि समाजसेवी आकाश धावना एवं प्रसिद्ध मोटेविथनल स्पीकर सौरभ जैन थे।अध्यक्षता श्रीमती मंजू श्री श्री माल ने की। उक्त अवसर पर श्री कुमार मेनन ने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ उससे ज्यादा आवश्यकता स्किल डेवलपमेंट की है ताकि बच्चे मल्टी टैलेंटेड हो और अपनी आत्म निर्भरता हेतु कई काम कर सकें।साथ ही उन्होंने अपनी ओर से बच्चों को



गणवेश प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ईश्वरीय शक्ति के चलते ये बच्चे किसी बात को सामान्य बच्चों से जल्द कैच करने में पारंगत होते हैं। विशिष्ट अतिथि आकाश धावना ने 1 बच्चे को गोद लेकर उसकी पढ़ाई भोजन में होने वाले खर्च का जिम्मा उठाते हुए कहा कि इन बच्चों को ईश्वर ने अतिरिक्त शक्ति प्रदान की है ये इशारे में ही अपने काम बड़ी पूर्ति

से करने की क्षमता रखते हैं। शेखर जैन ने खेल खेल में बच्चों को पढ़ने की आदत पर जोर दिया खासकर गणित और विज्ञान इनके रुचि के विषय बताया।मंजू श्री श्री माल ने इन बच्चों को समय समय पर स्पीच थेरेपी की मदद के साथ इनसे बोलने की आदत डालनी चाहिए कहा। संस्था के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने अतिथियों को जानकारी देते हुए बताया कि यह शाला निः शुल्क सारी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराती है जहाँ उच्च कोटि के भोजन से लेकर योग तथा आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा दी जाती है तो दूसरी ओर स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है।